

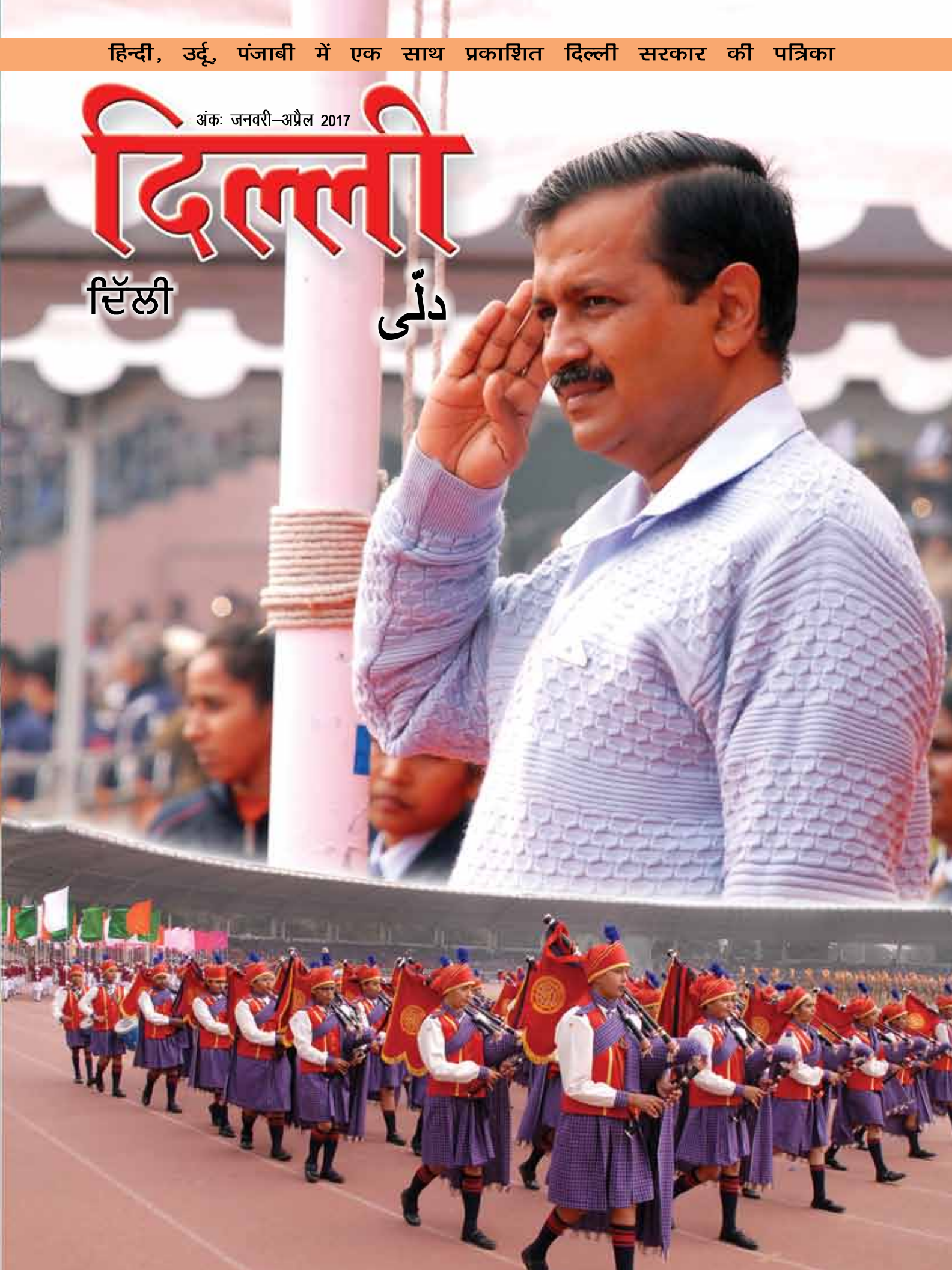
हिन्दी, उर्दू, पंजाबी में एक साथ प्रकाशित दिल्ली सरकार की पत्रिका

अंक: जनवरी-अप्रैल 2017

दिल्ली

दिल्ली

دہلی





गणतंत्र दिवस समारोह की झलकियाँ



दिल्ली

अंक : जनवरी-अप्रैल 2017

प्रधान सम्पादक

डॉ. जयदेव षडंगी

सम्पादक मंडल

संदीप मिश्र

डॉ. पंकज श्रीवास्तव

नलिन चौहान

कंचन आज़ाद

छाया चित्र

सुधीर कुमार, अजय कुमार, योगेश जोशी

“दिल्ली” पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार रचनाकारों के अपने हैं तथा दिल्ली सरकार का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं।

पत्राचार का पता

प्रधान सम्पादक

दिल्ली सूचना एवं प्रसार निदेशालय

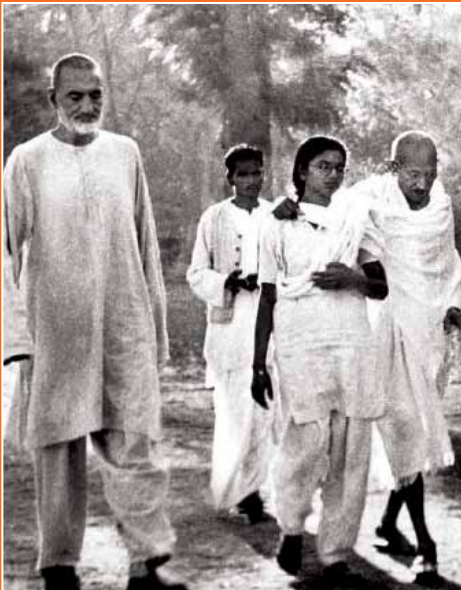
दिल्ली सरकार

खंड सं. 9, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

दूरभाष : 23819046, 23817926

फैक्स : 23814081

ई-मेल : delhidip@gmail.com



गाँधी जी का अंतिम दिन

8

14



इतिहास के झरोखे में

इस अंक में...

हिन्दी

दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई क्रांति	2
350 झुग्गीवालों को मिले पक्के मकान	6
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा	12
कहानी तिरंगे की	13
मैं रोज मोबाइल पर मेनीफेस्टो चेक करता हूँ	17
दो साल बेमिसाल	18
संक्षेप में	28

पंजाबी

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ	1
ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੈਨੀਫੇਸਟੋ ਚੈਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ - ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ	5
ਦੋ ਸਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ	6

उर्दू

1.....میں روزموبائل پر مینی فیسٹوچیک یوم جمہوریہ پروزیراعلی کا خطاب	
6.....کرتا ہوں: منیش سسودیا	
7.....دو سال بے مثال	



गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री का संबोधन

दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई क्रांति

दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह एक दिन पहले होता है। इस बार 25 जनवरी को छत्रसाल स्टेडियम में हुए रंगारंग कार्यक्रम के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में एक सपने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश की सभी सरकारें अगर शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत बेहतर बना दें तो आम लोग देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में इन दोनों क्षेत्रों में क्रांतिकारी सुधार हुआ है। पेश है मुख्यमंत्री के भाषण का लिखित रूप—

भारत माता की जय ! इन्कलाब जिंदाबाद !!

दिल्ली और देश के सभी नागरिकों को गणतंत्र की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हर साल हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि किस तरह स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों से लड़कर देश को आजाद कराया था। किस तरह उन्होंने संविधान सभा में बैठकर हमें इतना अच्छा संविधान दिया, बाबा साहेब के नेतृत्व में। इसी दिन 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। इतने वर्षों में देश को तमाम उपलब्धियाँ मिलीं और तमाम ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनमें काम करना बाकी है। आज से दो साल पहले दिल्ली के लोगों ने एक अभूतपूर्व काम करके दिखाया। आम आदमी राजनीति में आने से कतराता था। लेकिन दो साल पहले दिल्ली के लोगों ने यह धारणा बदल दी।

पिछले दो वर्षों में बहुत सारे अनुभव हुए, खट्टे-मीठे, अच्छे बुरे। आज मैं एक ऐसी बात रखना चाहता हूँ, जो सारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। अगर पूरा देश उसे अपना ले, तो बड़ी तेजी के साथ देश की प्रगति हो सकती है। मैं, मनीष जी और दूसरे कई साथी, राजनीति में आने के पहले समाज सेवी संस्थाओं में काम करते थे, गरीबों के बीच में। हमें कई ऐसे

पिछले दो वर्षों में बहुत सारे अनुभव हुए, खट्टे-मीठे, अच्छे बुरे। आज मैं एक ऐसी बात रखना चाहता हूँ, जो सारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। अगर पूरा देश उसे अपना ले, तो बड़ी तेजी के साथ देश की प्रगति हो सकती है।

बच्चे मिलते थे जो बहुत गरीब होते थे। उनके पास अच्छे स्कूलों में जाने के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन बड़े मेधावी होते थे। हमें लगता था कि अगर बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल जाए तो हमारे देश के लोग, देश को कहीं से कहीं पहुँचा सकते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत, संपत्ति, सड़कें, फ्लाईओवर, एयरपोर्ट, पहाड़, नदियाँ और जंगल नहीं हैं। सबसे बड़ी संपत्ति है—देश की जनता। पूरी दुनिया की सबसे समझदार जनता भारत में है।

हमें यह भी लगता था कि अगर देश के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दे दी जाएँ, उन्हें सेहतमंद बना दें तो वे देश को कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। हमारी सरकार बनी तो इन दो क्षेत्रों में हमने सबसे ज्यादा ध्यान दिया। कई लोग कहते हैं कि फलानी-फलानी सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में इतना खर्च करती है। मैं इसे खर्च नहीं, भविष्य के लिए निवेश मानता हूँ। कई गुना पैसा वापस आ जाएगा, जब लोग हृष्ट-पुष्ट हो जाएँगे।

पहले बजट के अंदर हमने शिक्षा का बजट दोगुना कर दिया। देश में लोगों को यकीन नहीं हुआ। बहुत सारी

एनजीओ और एक्सपर्ट्स, इस पर वाद-विवाद करते हैं। हमारे पास भी आते थे कि शिक्षा पर बजट को दस-बीस फीसदी बढ़ा दो। हमने सौ फीसदी बढ़ा दिया। वह हमारी कमिटमेंट थी। स्वास्थ्य का बजट डेढ़ गुना कर दिया। दो



साल में दिल्ली में जिस तरह से क्रांति आ रही है शिक्षा और स्वास्थ्य में उसकी चर्चा हर तरफ है। हालाँकि सब कुछ ठीक नहीं हो गया। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। गलतियाँ भी हो सकती हैं, जिन्हें ठीक करते जाएँगे। लेकिन गणतंत्र दिवस पर आप सबको संबोधित करते हुए सबसे ज्यादा संतुष्टि इसी बात की है कि हमने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम किया है।

जब हमारी सरकार बनी थी तो कोई भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल नहीं भेजना चाहता था। लोग पेट काटकर बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाना चाहते थे। दोस्तों, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ दिल्ली की जनता को, जिनके साथ मिलकर मनीष सिसोदिया, हमारे शिक्षा मंत्री ने, दो साल में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। कोशिश की गई है कि सभी सरकारी स्कूलों में पानी हो, साफ सुथरे टॉयलेट हों, बच्चियों के अलग टॉयलेट हों। सफाई और सुरक्षा का बेहतर इंतजाम किया गया है।

भला एक-एक क्लास में डेढ़-दो सौ बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं कोई टीचर इतने बच्चों को एक साथ कैसे पढ़ सकता है। आठ से दस हजार नए क्लासरूम दिल्ली में बने। लेकिन ये सारी बातें छोटी हैं। बड़ी बात यह है कि स्कूलों में पढ़ाई के स्तर में बहुत अच्छा परिवर्तन आया। इसके लिए मैं दिल्ली सरकार के सभी शिक्षकों

और प्रिंसिपलों को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने शानदार काम किया है। आज उन्हें विदेश में और आईआईएम में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। उनको लगने लगा है कि हमारी भी पूछ हो रही है। उन्हें लगने लगा है कि वे देश का भविष्य बना रहे हैं। उन्हीं शिक्षकों और प्रिंसिपलों ने यह चमत्कार करके दिखा दिया। मैं गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्हें सलाम करता हूँ।

मुझे खुशी है कि दिल्ली में जो नए सरकारी स्कूल बन रहे हैं, उनमें वे सारी सुविधाएँ हैं जो शायद आपको अच्छे से अच्छे निजी स्कूल में नहीं मिलेंगी। सरकारी स्कूलों में स्वीमिंग पूल बन रहे हैं। लिफ्ट लग रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में लोग निजी स्कूलों से बच्चों को निकाल कर सरकारी स्कूलों में एडमिट कराएँगे। दिल्ली के सरकारी स्कूल पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल होंगे।

निजी स्कूलों में भी कई हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम उन्हें सलाम करते हैं। लेकिन कहते हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसे ही कुछ निजी स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा को धंधा बना लिया है। जिन्होंने शिक्षा की दुकानें खोली हुई हैं। वे शिक्षा के नाम पर पैसा कमाना चाहते हैं। हम उनकी घोर निंदा करते हैं। उनके आचरण को ठीक करना सरकार की

जब हमारी सरकार बनी थी तो कोई भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल नहीं भेजना चाहता था। लोग पेट काटकर बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाना चाहते थे। दोस्तों, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ दिल्ली की जनता को, जिनके साथ मिलकर मनीष सिसोदिया, हमारे शिक्षा मंत्री ने, दो साल में क्रांतिकारी परिवर्तन किया।





जिम्मेदारी है। आज हमारा सिर्फ एक इंट्रेस्ट है कि दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और उचित फीस पर मिलनी चाहिए।

हमारी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को बेजा फीस बढ़ाने से रोका है। एडमिशन में डोनेशन पर रोक लगी है। ऐसा नहीं है कि सौ फीसदी रुक गया है। अब भी कुछ ऐसा कर रहे हैं। एडमिशन के लिए मेज के नीचे से ले रहे हैं पैसा, लेकिन मनीष सिसोदिया उनको ठीक करने में लगे हैं। जल्दी ही यह धिनौना डोनेशन सिस्टम खत्म होगा और नर्सरी के एडमिशन पूरी तरह पारदर्शी होंगे।

इसी तरह से दो साल में स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सुधार हुआ है। दिल्ली में बड़े अस्पतालों की कमी नहीं है। लेकिन अगर आपको छींक आ गई, बुखार और खॉंसी हो गई तो आपको एम्स जाना पड़ता है। इतनी भीड़ कि बिना सिफारिश इलाज नहीं हो पाता।

हमने मोहल्ला क्लीनिक बनाए जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। लंदन, पेरिस से पत्रकार देखने आए। संयुक्त राष्ट्र से एक्सपर्ट आये। अल्ट्रा माडर्न, एयरकंडीशन्ड, दवाएँ फ्री, जांच फ्री। ये क्लीनिक डेढ़ साल से चल रहे हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं। बहुत जल्दी एक हजार मोहल्ला क्लीनिक दिल्ली में बन जाएंगे। दो-तीन किलोमीटर के दायरे में कोई न कोई मोहल्ला क्लीनिक मिलेगा। छोटी-छोटी बीमारियों के बड़े अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा।

उसके ऊपर पॉलीक्लीनिक बनाए हैं। 122 पॉलीक्लीनिक बनेंगे पूरी दिल्ली में। वहाँ हड्डियों, महिलाओं और बच्चों समेत आठ विशेषज्ञ बैठते हैं। वहाँ पर एक्सरे और अल्ट्रासाउंड होता है। अगर कोई बड़ी बीमारी है तो सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में जा सकते हैं। दिल्ली के सारे

सरकारी अस्पतालों में सब लोगों के लिए दवाएँ मुफ्त कर दिया, टेस्ट मुफ्त कर दिया, सारा इलाज मुफ्त कर दिया। दिल्ली में सबके लिए फ्री इलाज की सुविधा है, चाहे अमीर हो या गरीब।

दोस्तों, हम रात दिन काम कर रहे हैं लेकिन लगता है कि अगर पूरा देश, सभी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार गणतंत्र दिवस पर ठान लें कि शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत ठीक करेंगे, तो आने वाले दिनों में देश बहुत प्रगति कर सकता है। जो बच्चे सामने बैठे हैं, वे बड़े होकर एडवोकेट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, एयरोप्लेन चलाएंगे और पूरी दुनिया में नाम रोशन करेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मेरा तो एक ही संदेश है कि पूरा देश ठान ले कि शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर करना है। अच्छी बात है कि प्राइवेट स्कूल हैं, अच्छी बात है कि प्राइवेट अस्पताल हैं, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर पर नहीं छोड़ सकते।

हम लोगों ने दिल्ली में इसी दिशा में कदम उठाया है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। दिल्ली की जनता से जिस तरह का समर्थन और प्यार मिलता रहा है, उसे देखते हुए हमें

यकीन है कि हम अपने मिशन में जरूर कामयाब होंगे।

“भारत माता की जय !” ■



दो साल में स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सुधार हुआ है। दिल्ली में बड़े अस्पतालों की कमी नहीं है। लेकिन अगर आपको छींक आ गई, बुखार और खॉंसी हो गई तो आपको एम्स जाना पड़ता है। इतनी भीड़ कि बिना सिफारिश इलाज नहीं हो पाता। हमने मोहल्ला क्लीनिक बनाए जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है।

350 झुग्गीवालों को मिले पक्के मकान

अब गरीबों के सपनों में नहीं आएगा बुलडोज़र !

6 फरवरी को दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में नेहरू कैंप की झुग्गी के लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे। घर तो इन गरीबों को पहले भी कई बार छोड़ना पड़ा था, लेकिन इस बार एक फर्क था। इस बार वे उजड़ नहीं रहे थे बल्कि बस रहे थे। दिल्ली सरकार ने उन्हें पक्के मकान देने का वादा पूरा कर दिया था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई सरकार अपना वादा इतनी संजीदगी से पूरा कर सकती है। एक ख्वाब हकीकत बनकर सामने था। कई तो खुशी के मारे रो रहे थे। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इन सभी को फ्लैट के कागजात सौंपे। उन्होंने इस मौके पर यह संदेश दिया —

दस साल पहले जब झुग्गी टूट रही थी तो हम रात भर यहीं लेटे थे। प्लानिंग करते वक्त सोचना होगा कि लोगों के घर में अखबार डालने वाला कहाँ रहेगा? जो सब्जी बेचने वाला है, वह कहाँ रहेगा? उनके बच्चों की साइकिल पंचर हो जाएगी तो पंचर लगाने वाला कहाँ रहेगा?

“आज दिल्ली के लिए बड़ा दिन है। 25—30 साल से लोग झुग्गियों में रह रहे होते थे। बच्चे बड़े हो जाते थे, उनकी शादी हो जाती थी। फिर भी हटाया जाता था। आज सब लोग मिठाई खाकर हट रहे हैं। ऐसा दो साल में कई बार हुआ है।

दस साल पहले जब झुग्गी टूट रही थी तो हम रात भर यहीं लेटे थे। प्लानिंग करते वक्त सोचना होगा कि लोगों के घर में अखबार डालने वाला कहाँ रहेगा? जो सब्जी बेचने वाला है, वह कहाँ रहेगा? उनके बच्चों की साइकिल पंचर हो जाएगी तो पंचर लगाने वाला कहाँ रहेगा? कार साफ



दिल्ली में बनेंगे 6178 फ्लैट

आवासीय परिसरों की कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार 6178 नए फ्लैट बनाएगी। ये फ्लैट आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए होंगे और दिल्ली शहरी आश्रय विकास बोर्ड के माध्यम से यह कार्य किया जाएगा।

इस पर करीब 866 करोड़ खर्च होंगे। इसके लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। ये आवास लाजपत नगर, भलस्वा, देव नगर, मंगोलपुरी व अम्बेडकर नगर में तैयार होंगे। दिल्ली सरकार ने इस योजना को पॉयलट प्रोजेक्ट के तहत स्वीकृति प्रदान की है।

करने वाले या दूध देने वाले कहाँ रहेंगे — इसकी प्लानिंग नहीं होती। यह हमारी सोच की प्रॉब्लम है।

ऐसे में ऑटो वाले, सिलाई करने वाले दूध देने वाले तो आएँगे। दिल्ली में 675 झुग्गी कालोनियाँ हैं, जिनमें करीब तीस लाख लोग रहते हैं। ये बदमाश लोग नहीं हैं। जबरदस्ती नहीं आए। काम करने आये हैं। हमारी सरकार का कमिटमेंट है कि इन्हें ऐसे नहीं उजड़ने देंगे। इसके पहले कानून था कि 2006 तक की झुग्गियों के लिए ही काम करेंगे। उसके बाद के लिए नहीं। हम जब सरकार में आए तो एक महीने पहले तक यानी 1 जनवरी 2015 की समय सीमा तय कर दी गई। इसके पहले की की सारी झुग्गियों को वैध माना जाएगा।

कुछ लोग तो ऐसे हैं, जो सोचते हैं कि सरकार फ्लैट दे रही है एक झुग्गी डाल लें। ये बेईमानी रोकना सरकार का काम है। जो पहले से हैं, उन्हें बढ़िया घर देना, हमारी प्राथमिकता है। आसान काम नहीं है। धीरे-धीरे देंगे।

सरकार की मंशा साफ है। अफसरों की मंशा परेशान करने की नहीं है। वे बैठेंगे जैसे घर का बड़ा भाई बैठता है। कुछ साथी हैं जो विकलांग है, उनका फ्लैट ऊपरी मंजिल पर निकला, उनका बदलकर के नीचे कर दिया।

इसकी बाद भी शिकायत रह जाए तो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनी कमेटी से दूर कराएँगे। अब आप सारे लोग ऐसी जगह जा रहे हो कि सपने में भी बुलडोजर नहीं आएगा। पाँच वर्षों तक इन घरों का मेन्टीनेंस सरकार करेगी। बच्चों का एडमिशन नए स्कूलों में वहीं कराया जाएगा। जिनका इम्तहान है, उन बच्चों को पुराने स्कूल आने-जाने के लिए बस का इंतजाम होगा।” ■





गाँधी जी का अंतिम दिन!

शुक्रवार 30 जनवरी 1948 की वह सुबह आम दिनों की तरह ही थी। तब किसको पता था कि शाम को क्या होने वाला है। हम हमेशा की तरह साढ़े तीन बजे अपनी प्रार्थना के लिए उठे।

उसके बाद रोज की गतिविधियां शुरू हो गईं। गाँधी जी ने अपनी पोती आभा को जगाया। इसके बाद उन्होंने स्नान किया और फिर गद्दे पर बैठ गए। उनका दिन हमेशा प्रार्थना के साथ शुरू होता था। उनकी प्रार्थनाओं में सभी धर्मों की पवित्र पुस्तकों की बातें शामिल होती थीं, खासकर हिंदू धर्म और इस्लाम की।

गाँधी जी ने ध्यान में अपनी आंखें बंद कर लीं। आभा अभी भी सोई हुई थी। गाँधीजी ने उसकी अनुपस्थिति महसूस कर ली थी। प्रार्थना आभा के बिना ही हुई। प्रार्थना के तुरंत बाद मनु रसोई में चली गईं। रोज की तरह उसने गाँधीजी का प्रिय पेय—एक चम्मच शहद और नींबू के रस वाला गरम पानी का एक गिलास तैयार किया। जब उसने

गिलास गाँधीजी को पकड़ाया तो उन्होंने कहा, 'लगता है मेरा असर अपने साथ के लोगों पर भी कम होता जा रहा है। प्रार्थना झाड़ू की तरह है जिसका मकसद है हमारी आत्मा की शुद्धि। प्रार्थना में आभा के न आने से मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुम्हें तो पता ही है कि मैं प्रार्थना को कितना महत्वपूर्ण मानता हूँ। अगर तुममें साहस हो तो तुम मेरी तरफ से मेरी अप्रसन्नता उस तक पहुंचा सकती हो। अगर वह प्रार्थना में आने की इच्छुक नहीं है तो उसे मेरा साथ छोड़ देना चाहिए। इसमें हम दोनों की भलाई होगी!'

इस दौरान आभा जग चुकी थी और उसने अपना काम शुरू कर दिया था। गाँधी जी उससे सीधे मुखातिब नहीं हो रहे थे जिसकी वजह वे ही जानते होंगे। मैं दिन भर के निर्देश लेने के लिए उनके पास बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि दो फरवरी से उनका जो दस दिन का सेवाग्राम का दौरा शुरू हो रहा है, मैं उसके लिए व्यवस्था करूँ। मैंने उनके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए संविधान का वह टाइप किया हुआ ड्राफ्ट रखा जो उन्होंने एक दिन पहले मुझसे बोलकर लिखवाया था और जिसमें उन्होंने कांग्रेस को भंग करने और एक नए संगठन के निर्माण का सुझाव दिया था, जिसका समाज सेवा और ग्रामीण

क्षेत्रों की बेहतरी पर और ज्यादा जोर हो। उनका इसे देखने का मन नहीं था। उन्होंने मेरे वरिष्ठ प्यारेलाल जी को बुलाया और यह ड्राफ्ट उन्हें दे दिया। इस निर्देश के साथ कि वे इसे सावधानी से देखें और अगर कोई सुझाव या सुधार जरूरी लगे तो बताएँ।

मैं अब ज़्यादा लंबा जीना नहीं चाहता

उन दिनों दिल्ली में हालात सामान्य से कोसों दूर थे। पाकिस्तान से आ रही हिंदू शरणार्थियों की एक विशाल आबादी के चलते सांप्रदायिक तनाव बना हुआ था। पाकिस्तान में मुसलमानों के हाथों बुरा अनुभव झेल चुके ये लोग दिल्ली में रह रहे मुसलमानों से इसका बदला लेना चाहते थे। मुस्लिम और हिंदू नेताओं के जत्थे रोज उनसे मिलते और राजधानी में सामान्य हालात कैसे बहाल हों, इस पर चर्चा करते।

सर्दियों का मौसम था और गाँधी जी अक्सर खुले लॉन में चारपाई पर बैठकर धूप सेंकते हुए दिन बिताते। उनसे मिलने वालों का तांता लगा रहता था। वे कभी खाली बैठे नहीं दिखते थे। जब पहले तय कोई मुलाकात न होती तो वे चिट्ठियाँ और गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में लेख लिखने में व्यस्त रहते। मंत्री और दूसरे वीआईपी उनसे वक्त लेकर मुलाकात करते जबकि पंडित नेहरू जब दिल्ली होते तो अपने दफ्तर जाते हुए रोज करीब नौ बजे उनसे मिलते।

उस दिन गाँधी जी से जो मशहूर हस्तियां मिलने आईं उनमें श्रीमती आर.के. नेहरू भी थीं। वे सुबह छह बजे आई थीं और दोपहर में उन्हें अमेरिका जाना था। उनके अनुरोध पर गाँधीजी ने उन्हें अपने दस्तखत के साथ एक फोटो दिया जिस पर लिखा था, 'आप एक गरीब देश की प्रतिनिधि हैं और इस नाते आप वहाँ सादा और मितव्यय तरीके से रहें।' करीब दो बजे लाइफ मैगजीन के मशहूर

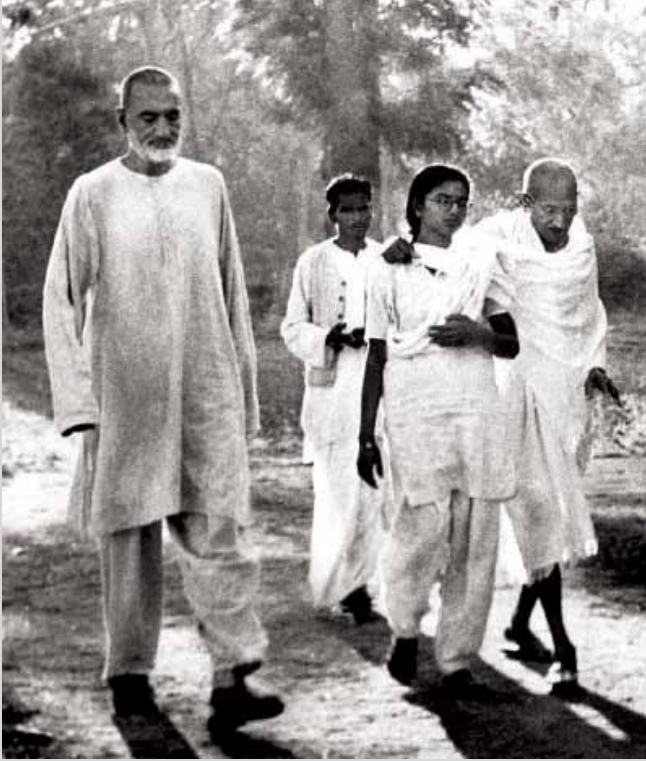


फोटोग्राफर मार्ग्रेट बर्क ने गाँधीजी का साक्षात्कार लिया। इस दौरान उन्होंने पूछा, 'आप हमेशा कहते रहे हैं कि मैं 125 साल तक जीना चाहूँगा। यह उम्मीद आपको कैसे है?' गाँधीजी का जवाब उन्हें हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि अब उनकी ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। जब मार्ग्रेट ने इसकी वजह पूछी तो उनका कहना था, 'क्योंकि दुनिया में इतनी भयानक चीजें हो रही हैं। मैं अंधेरे में नहीं रहना चाहता।'

बिड़ला भवन में उनका ज्यादातर वक्त चिट्ठियां लिखने, लोगों से मिलने और प्रार्थना में गुजरता था। मार्ग्रेट के जाने के बाद प्रोफेसर एनआर मलकानी दो व्यक्तियों के साथ आए। पाकिस्तान में हमारे डिप्टी हाई कमिश्नर मलकानी ने गाँधीजी को सिंध के हिंदुओं की दुर्दशा बताई। उनकी बात धैर्य के साथ सुनने के बाद गाँधी जी ने कहा, 'अगर लोगों ने मेरी सुनी होती तो ये सब नहीं होता। मेरा कहा लोग मानते नहीं। फिर भी जो मुझे सच लगता है मैं कहता रहता हूँ। मुझे पता है कि लोग मुझे पुराने जमाने का आदमी समझने लगे हैं।'

बीबीसी के बॉब स्टिमसम को प्रार्थना के बाद गाँधी जी से मिलना था। उन्होंने अपने कुछ सवाल पहले ही दे दिए थे और वे आकर सीधे लॉन में पहुंच गए थे जहाँ गाँधीजी को अपनी प्रार्थना सभा करनी थी। मुख्यमंत्री यूएन डेबर और काठियावाड़ से रसिकलाल पारेख बिना समय लिए उनसे मिलने आए थे और चर्चित लेखक विंसेंट शेयान भी, जिन्होंने बीते कुछ दिनों के दौरान गाँधीजी के साथ





कुछ इंटरव्यू किए थे, उन सभी को निराश होना पड़ा। बिड़ला भवन के गेट पर उसका अपना चौकीदार भी तैनात रहता था।

बीते साल गाँधीजी की सभाओं के दौरान कुरान की आयतों के पाठ पर आपत्तियाँ जताई गई थीं और इसलिए सरदार पटेल ने गृहमंत्री के तौर पर एहतियाती उपाय बरतते हुए बिड़ला भवन में एक हेड कांस्टेबल और चार कांस्टेबलों की नियुक्ति का आदेश दिया था।

गाँधीजी की प्रार्थना सभा में बम धमाका

20 जनवरी की प्रार्थना सभा में एक बम धमाका हुआ था। यह बम मदन लाल नाम के एक पंजाबी शरणार्थी ने फेंका था, लेकिन यह गाँधी जी को नहीं लगा। इससे एक दीवार टूट गई थी। पुलिस का कहना था कि गाँधी जी की जान को खतरा है और तलाशी होनी चाहिए। लेकिन गाँधी जी कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सुरक्षा की चर्चा करने पहुँचे पुलिस के डीआईजी को बताया कि उनका जीवन ईश्वर के हाथ में है, अगर उनकी मृत्यु ही लिखी हुई है तो कोई भी सुरक्षा उन्हें नहीं बचा सकती। उनका कहना था, 'जो आजादी के बजाय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं उन्हें जीने का हक नहीं है।' लोगों की तलाशी के लिए सहमत होने की बजाय वे प्रार्थना सभा रोक दोपहर दो बजे आभा और मनु, गाँधी जी से आज्ञा लेकर कुछ दोस्तों से मिलने चली गई। इस वादे के साथ कि शाम की प्रार्थना के लिए वे समय से वापस आ जाएंगी। गाँधी जी को शाम का खाना परोसने की जिम्मेदारी मुझ पर

आ गई। हालांकि सरकार बने अभी सिर्फ पाँच महीने ही हुए थे, लेकिन मीडिया में पंडित नेहरू और सरदार पटेल के मतभेदों की खबरें जमकर छप रही थीं। गाँधी जी इन अफवाहों से परेशान थे और इस समस्या का हल ढूँढना चाहते थे। वे तो यहां तक सोच रहे थे कि सरदार पटेल को इस्तीफा देने के लिए कह दें। उन्हें लगता था कि शायद इससे देश चलाने के लिए नेहरू को पूरी तरह से खुला हाथ मिल जाएगा। उन्होंने चार बजे पटेल को चर्चा के लिए बुलाया था और वे चाहते थे कि प्रार्थना के बाद वे इस मुद्दे पर बात करें। अपनी बेटी मणिबेन के साथ पटेल जब पहुँचे तो गाँधी जी खाना खा रहे थे। वे बातचीत कर ही रहे थे कि आभा और मनु भी वहां पहुँच गई।

सरदार पटेल के साथ आखिरी मुलाकात

प्रार्थना का समय पाँच बजे था। लेकिन गाँधी जी और पटेल के बीच बातचीत पांच बजे के बाद भी जारी रही। बातों की अहमियत और गंभीरता को देखते हुए हममें से किसी की भी बीच में बोलने की हिम्मत नहीं हुई। लड़कियों ने सरदार पटेल की बेटी मणिबेन को इशारा किया और पाँच बजकर दस मिनट पर बातचीत खत्म हो गई। इसके बाद गांधीजी शौचालय गए और फिर फौरन ही प्रार्थना वाली जगह की तरफ बढ़ चले जो करीब 30-40 गज की दूरी पर रही होगी। कमरे से बाहर निकलते ही चार या पांच सीढ़ियाँ थीं और फिर लॉन शुरू हो जाता था।

गाँधी जी को प्रार्थना सभा में पहुँचने में 15 मिनट की देर हो गई थी। करीब 250 लोग बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे थे। थोड़ी सी दूरी से मैं देख सकता था कि भीड़ की नजर गाँधीजी के कमरे की तरफ लगी हुई है। जैसे ही वे निकले मैंने लोगों को कहते सुना, 'गाँधी जी आ गए।' सभी लोगों की गर्दन उसी दिशा में घूम गई



जहाँ से गाँधी जी आ रहे थे। हमेशा की तरह गाँधीजी चुस्त चाल के साथ सिर झुकाए चल रहे थे और उनकी नजर जमीन पर जमी हुई थी। उनके हाथ अपनी दोनों पोतियों के कंधे पर थे। करीब ही बाईं तरफ से मैं उनके पीछे-पीछे चल रहा था।

मैंने उन्हें लड़कियों को डाँट लगाते सुना। वे इसलिए नाराज थे कि प्रार्थना के लिए देर हो रही है, यह उन्हें क्यों नहीं बताया गया।

उनका कहना था, 'मुझे देर हो गई है, मुझे यह अच्छा नहीं लगता।' जब मनु ने कहा कि इतनी गंभीर बातचीत को देखते हुए वह इसमें बाधा नहीं डालनी चाहती थी तो गाँधी जी ने जवाब दिया, 'नर्स का कर्तव्य है कि वह मरीज को सही वक्त पर दवाई दे। अगर देर होती है तो मरीज की जान जा सकती है।'



जब नाथूराम गोडसे ने गोलियाँ चलाई

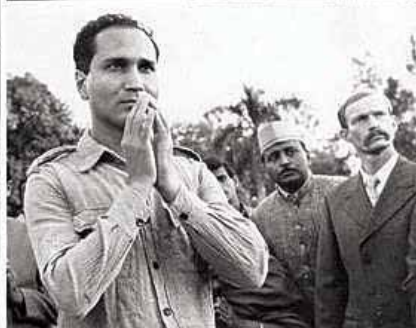
हम उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगे जो प्रार्थना के लिए बने मंच तक जा रही थीं। लोग हाथ जोड़कर गाँधी जी का अभिवादन कर रहे थे और वे भी जवाब दे रहे थे। सीढ़ियों से 25 फुट दूर एक फुट ऊँचा लकड़ी का वह आसन बना था जिस पर वे बैठते थे। लोग उनके लिए जगह बनाते हुए एक तरफ हो रहे थे। अपनी जेब में रिवॉल्वर रखे हत्यारा (नाथूराम गोडसे) इस भीड़ में ही मौके का इंतजार कर रहा था। गाँधी जी मुश्किल से पाँच या छह कदम ही आगे बढ़े होंगे कि उसने बहुत करीब से एक के बाद एक गोलियाँ तेजी से दाग दीं। उनकी फौरन मृत्यु हो गई। वे पीछे गिर पड़े उनके घावों से काफी मात्रा में खून बहे जा रहा था और इस घटना से मची भगदड़ में उनका चश्मा और खड़ाऊँ न जाने कहां छिटक गए थे। मैं अपनी जगह

पर जड़ रह गया। बाद में अकेले में यह दृश्य याद करके मेरी आँखों से आंसू बह निकले थे।

खबर तेजी से फैली। कुछ ही मिनटों में बिड़ला भवन के बाहर भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई और लोगों को अंदर घुसने से रोकने के लिए गेट बंद करना पड़ा। पटेल तब तक जा चुके थे। मैं अपने कमरे की तरफ भागा और फोन से नेहरू के दफ्तर तक यह खबर भिजवाई। उन



दिनों हम मंत्रियों के घरों में बेधड़क जा सकते थे। मैं किसी तरह से भीड़ के बीच से निकलते हुए कार में बैठा और इस घटना की खबर देने के लिए मुश्किल से पाँच मिनट की दूरी पर स्थित पटेल के घर की तरफ चला।



इस दौरान गाँधी जी की पार्थिव देह उठाकर उनके कमरे तक लाई जा चुकी थी। वे चटाई पर पड़े थे और लोग

उनके इर्द-गिर्द बैठे थे। ऐसा लगता था जैसे वे सोए हों। उनका शरीर कुछ समय तक गर्म ही था। रात आंसुओं में बीती। सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की नहीं बल्कि दुनिया भर में उन करोड़ों लोगों की भी, जिनके लिए गाँधी जी जिए और मरे।

जब उनकी देह उठाकर उनके कमरे तक लाई गई तो उसके बाद वहाँ हंगामा मच गया। लोग गाँधी जी की याद के लिए उस जगह की मिट्टी उठाने लगे जहाँ वे गोली लगने के बाद गिरे थे। एक-एक मुट्ठी करते-करते कुछ ही घंटों के भीतर वहाँ पर एक बड़ा गड्ढा हो गया। इसके बाद उस जगह की घेरेबंदी कर वहाँ एक गार्ड तैनात कर दिया गया।

(महात्मा गाँधी के निजी सचिव वी.कल्याणम् द्वारा वर्णित आँखों देखा हाल का संपादित अंश) ■



विजयी विश्व तिरंगा प्यारा

विजयी विश्व तिरंगा प्यारा,
झंडा ऊंचा रहे हमारा।

सदा शक्ति बरसाने वाला,
प्रेम सुधा सरसाने वाला,

वीरों को हरशाने वाला,
मातृभूमि का तन-मन सारा।। झंडा...।

स्वतंत्रता के भीषण रण में,
लखकर बढ़े जोश क्षण-क्षण में,

कांपे शत्रु देखकर मन में,
मिट जाए भय संकट सारा।। झंडा...।

इस झंडे के नीचे निर्भय,
लें स्वराज्य यह अविचल निश्चय,

बोलें भारत माता की जय,
स्वतंत्रता हो ध्येय हमारा।। झंडा...।

आओ! प्यारे वीरो, आओ।
देश-धर्म पर बलि-बलि जाओ,

एक साथ सब मिलकर गाओ,
प्यारा भारत देश हमारा।। झंडा...।

इसकी शान न जाने पाए,
चाहे जान भले ही जाए,

विश्व-विजय करके दिखलाएं,
तब होवे प्रण पूर्ण हमारा।। झंडा...।

विजयी विश्व तिरंगा प्यारा,
झंडा ऊंचा रहे हमारा।

रचनाकाल: 1924

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान धूम मचाने वाले झण्डा गीत 'विजयी विश्व तिरंगा प्यारा' लिखने वाले श्यामलाल गुप्त 'पार्षद' (जन्म: 16 सितम्बर 1893 — मृत्यु: 10 अगस्त 1977) भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक सेनानी, पत्रकार, समाजसेवी एवं अध्यापक थे। वर्ष 1921 में गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आये तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन में सहभागिता की। पार्षद जी ने एक व्यंग्य रचना लिखी जिसके लिये तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने आपके ऊपर 500 रुपये का जुर्माना लगाया। उन्होंने वर्ष 1924 में झंडागान की रचना की, जिसे 1925 में कानपुर में कांग्रेस के सम्मेलन में पहली बार झंडारोहण के समय सार्वजनिक रूप से सामूहिक रूप से गाया गया। फिर यह आजादी का तराना बन गया। 1938 में सुभाषचंद्र बोस की अध्यक्षता में हरिपुरा में हुए काँग्रेस अधिवेशन में इसे औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। पार्षद जी ने 1952 में लाल किले से प्रसिद्ध 'झंडा गीत' गाया। ■



कहानी तिरंगे की



तिरंगा हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है। तिरंगे का नाम आते ही हमारा सिर गर्व से उठ जाता है और शरीर में देशप्रेम की भावना की लहर दौड़ पड़ती है। लेकिन क्या आपको पता है तिरंगे के बनने के पीछे कहानी क्या है। आजादी के आंदोलन के दौरान जिस स्वराजध्वज को स्वीकार किया गया था वह भी तिरंगा ही था, लेकिन उसके बीच में चक्र नहीं चरखा था।

आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या हो, इसके लिए लगातार 5 सालों तक रिसर्च किया गया। इतना ही नहीं इस अवधि में लगभग 30 देशों के झंडों पर अध्ययन हुआ। तब जाकर भारत का राष्ट्रीय ध्वज का यह स्वरूप तय किया गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में तिरंगे को देश के झंडे के रूप में स्वीकार किया गया।

तिरंगे का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में जन्मे पिंगली भी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे। पिंगली वेंकैया ने एक

ऐसे ध्वज की कल्पना की जो सभी भारतवासियों को एक सूत्र में बांध दे। उनकी इस पहल को एस.बी. बोमान जी और उमर सोमानी जी का साथ मिला और इन तीनों ने मिल कर नेशनल फ्लैग मिशन का गठन किया।

वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज के लिए महात्मा गांधी से सलाह ली और गांधी जी ने उन्हें इस ध्वज के बीच में अशोक चक्र रखने की सलाह दी जो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का संकेत बने। उन्होंने 5 सालों तक 30 देशों के झंडों पर रिसर्च किया और इस रिसर्च के नतीजे के तौर पर भारत को राष्ट्रध्वज तिरंगा मिला।

फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत झंडा खादी से ही बन सकता है और इसे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ही फहराया जाता था। लेकिन 2005 में एक याचिका की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अन्य अवसरों पर भी झंडा फहराने की अनुमति देने का निर्देश दिया। तब से आम लोग भी इस झंडे को फहरा सकते हैं। ■

इतिहास के झरोखे में दिल्ली की 26 जनवरी

—नलिन चौहान

आज के दौर की नई पीढ़ी को शायद यह बात पता नहीं होगी कि देश की राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस राजपथ की बजाय इर्विन स्टेडियम (आज का नेशनल स्टेडियम) में हुआ था। उस समय नेशनल स्टेडियम के चारों तरफ चारदीवारी नहीं थी लिहाजा पृष्ठभूमि में पुराना किला साफ दिखता था।

यह एक अल्पज्ञात सत्य है कि सन् 1950 से 1954 के मध्य गणतंत्र दिवस का समारोह कभी इर्विन स्टेडियम, किंग्सवे, लाल किला तो कभी रामलीला मैदान में हुआ न कि राजपथ पर। सन् 1955 से ही राजपथ पर नियमित रूप से गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत हुई। तब से

आज तक ऐसा ही हो रहा है कि 8 किलोमीटर लंबी परेड की शुरुआत रायसीना हिल से होती है और वह राजपथ, इंडिया गेट से गुजरती हुई लालकिला तक जाती है।

देश के स्वतंत्र होने और भारतीय संविधान के प्रभावी होने से पूर्व 26 जनवरी की तिथि का अपना महत्त्व था। आधुनिक भारत के इतिहास में 26 जनवरी को विशेष दिवस के रूप में चिह्नित किया गया था और उसका कारण था कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करके यह घोषणा की गई थी, यदि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी, 1930 तक भारत को उपनिवेश का



पद (डोमीनियन स्टेट्स) नहीं प्रदान करेगी तो भारत अपने को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर देगा।

26 जनवरी, 1930 तक जब अंग्रेज सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया तब कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि में राष्ट्र को स्वतंत्र बनाने की पहल करते हुए भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की और अपना सक्रिय आंदोलन आरंभ किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस लाहौर अधिवेशन में पहली बार तिरंगे झंडे को फहराया गया और साथ ही प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का भी निर्णय लिया गया। इस तरह 26 जनवरी, अघोषित रूप से भारत का स्वतंत्रता दिवस बन गया था। उस दिन से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा।

सन् 1950 में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने जनवरी के 26वें दिन बृहस्पतिवार को सुबह दस बजने के अठारह मिनट बाद भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। इसके छह मिनट बाद बाबू राजेंद्र प्रसाद को गणतांत्रिक भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। उस समय गवर्मेंट हाउस कहलाने वाले मौजूदा राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में राजेंद्र बाबू के शपथ लेने के बाद दस बजकर 30 मिनट पर तोपों की सलामी दी गई, यह परंपरा 70 के दशक तक बनी रही फिर बाद में 21 तोपों की सलामी दी जाने लगी जो कि आज तक कायम है।

राष्ट्रपति का कारवाँ दोपहर बाद ढाई बजे गवर्मेंट हाउस (आज के राष्ट्रपति भवन) से इर्विन स्टेडियम (आज का नेशनल स्टेडियम) के लिए रवाना हुआ और कर्नॉट प्लेस व आसपास के क्षेत्रों का चक्कर लगाते हुए पौने चार बजे सलामी मंच तक पहुंचा। राजेंद्र बाबू पैंतीस साल पुरानी लेकिन विशेष रूप से सुसज्जित बग्घी में सवार हुए, जिसमें छह बलिष्ठ ऑस्ट्रेलियाई घोड़े जुते हुए थे। इर्विन स्टेडियम में हुई मुख्य परेड को देखने के लिए 15 हजार लोग मौजूद थे।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इरविन स्टेडियम में झंडा फहराकर परेड की सलामी ली। इस परेड में सशस्त्र सेना के तीनों बलों ने हिस्सा लिया, जिसमें नौसेना, इन्फैंट्री, कैवेलरी रेजीमेंट, सर्विसेज रेजीमेंट के अलावा सेना के सात बैंड

भी शामिल हुए थे। आज भी यह परंपरा कायम है। पहले गणतंत्र दिवस से ही मुख्य अतिथि बुलाने की परंपरा बनाई गई, सन् 1950 में पहले मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। पहली बार, इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया।

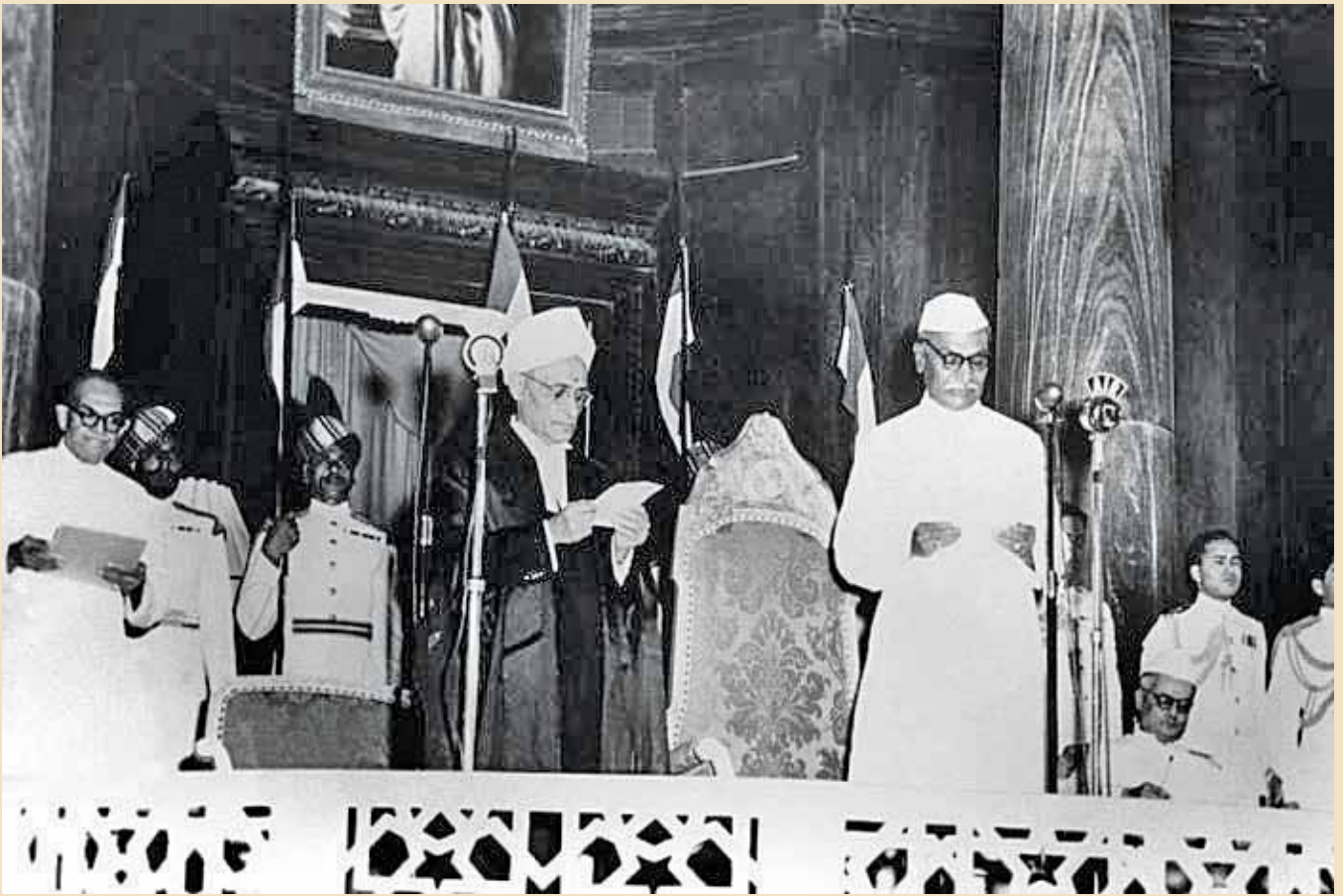
सन् 1951 से गणतंत्र दिवस का समारोह किंग्स-वे (आज का राजपथ) पर होने लगा, जिससे उसमें अधिकांश नागरिकों की भागदौरी को देख सकें। उस समय जनपथ क्वींस-वे के नाम से जाना जाता था। रक्षा जनसंपर्क निदेशालय के दस्तावेजों और सैनिक समाचार पत्रिका के पुराने अंकों के अनुसार, 1951 के गणतंत्र दिवस समारोह में चार वीरों को वीरता के लिए सर्वोच्च अलंकरण परमवीर चक्र प्रदान किए गए। उस वर्ष से समारोह सुबह हुआ था और परेड गोल डाकखाना पर खत्म हुई थी।

सन् 1952 से बीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम आरंभ हुआ। इसका एक समारोह रीगल सिनेमा के सामने मैदान में और दूसरा लालकिले में हुआ। सेना बैंड ने पहली बार महात्मा गाँधी के मनपसंद गीत 'अबाइड विद मी' की धुन बजाई और तभी उसे प्रतिवर्ष यह धुन बजती है। सन् 1953 में पहली बार लोक नृत्य और आतिशबाजी को सम्मिलित किया गया। उस समय आतिशबाजी रामलीला मैदान में होती थी। उसी वर्ष पूर्वोत्तर राज्यों—त्रिपुरा, असम और नेफा (अब अरुणाचल प्रदेश) के वनवासी बंधुओं को समारोह में बुलाया गया।

जबकि सन् 1955 में महाराणा प्रताप के अनुयायी और राजस्थान के गाड़ोलिया लुहारों ने पहली बार समारोह में भाग लिया। उस वर्ष परेड दो घंटे से ज्यादा चली। सन् 1954 में में एनसीसी की लड़कियों के दल ने पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया।

सन् 1955 में लाल किले के दीवान-ए-आम में गणतंत्र दिवस पर मुशायरे की परंपरा शुरू हुई। उस समय मुशायरा रात दस बजे शुरू होता था। उसके बाद के साल में हुए 14 भाषाओं के कवि सम्मेलन रेडियो से प्रसारित हुआ।

सन् 1956 में पहले बार गणतंत्र दिवस परेड में पांच सजे धजे हाथियों को सम्मिलित हुए। विमानों के शोर से हाथियों के बिदकने की आशंका के चलते सेना की



टुकड़ियों के गुजरने और लोक नर्तकों की टोली आने के बीच के समय में हाथियों को लाया गया तब हाथियों पर शहनाई वादक बैठे थे। सन् 1958 से राजधानी में सरकारी भवनों पर रोशनी करने की शुरुआत हुई। सन् 1959 से गणतंत्र दिवस समारोह में दर्शकों पर वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से फूल बरसाने की शुरुआत हुई।

सन् 1960 में पहली बार बहादुर बच्चों को हाथी के हौदे पर बैठाकर लाया गया जबकि बहादुर बच्चों को सम्मानित करने की शुरुआत हो चुकी थी। उस साल, दिल्ली में 20 लाख लोगों ने गणतंत्र दिवस समारोह देखा जिनमें से पांच लाख लोग तो राजपथ पर ही जमा थे। बाकी लोग दिल्ली के जिन इलाकों से परेड गुजरी वहां से इसे देखा।

गणतंत्र दिवस परेड और बीटींग रिट्रीट समारोह के लिए टिकटों की बिक्री 1962 में शुरू की गई। उस साल तक गणतंत्र दिवस परेड की लंबाई छह मील हो गई थी यानी जब परेड की पहली टुकड़ी लाल किला पहुंच गई तब आखिरी टुकड़ी इंडिया गेट पर ही थी! उसी वर्ष चीनी हमले के कारण अगले साल परेड का आकार छोटा कर

दिया गया। सन् 1963 के गणतंत्र समारोह में फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार, पार्श्व गायक तलत महमूद और शीर्ष पार्श्व गायिका लता मंगेशकर ने प्रधानमंत्री कोष के लिए कार्यक्रम पेश कर कोष एकत्र किए।

चीन के विरुद्ध युद्ध में शौर्य-वीरता दिखाने वाले सैनिकों और शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करने लिहाज से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों सहित असंख्य नागरिकों ने राष्ट्रपति मंच के सामने परेड में भाग लिया। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पहली बार 26 जनवरी के संचलन में सहभागिता का निमंत्रण मिला और परिणामस्वरूप उसके 3,000 स्वयंसेवक अपने पूर्ण गणवेश तथा घोष के साथ संचलन में सहभागी हुए।

सन् 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहली बार इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति पर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और तब से यह परंपरा जारी है।

मैं रोज़ मोबाइल पर मेनीफ़ेस्टो चेक करता हूँ-मनीष सिसोदिया

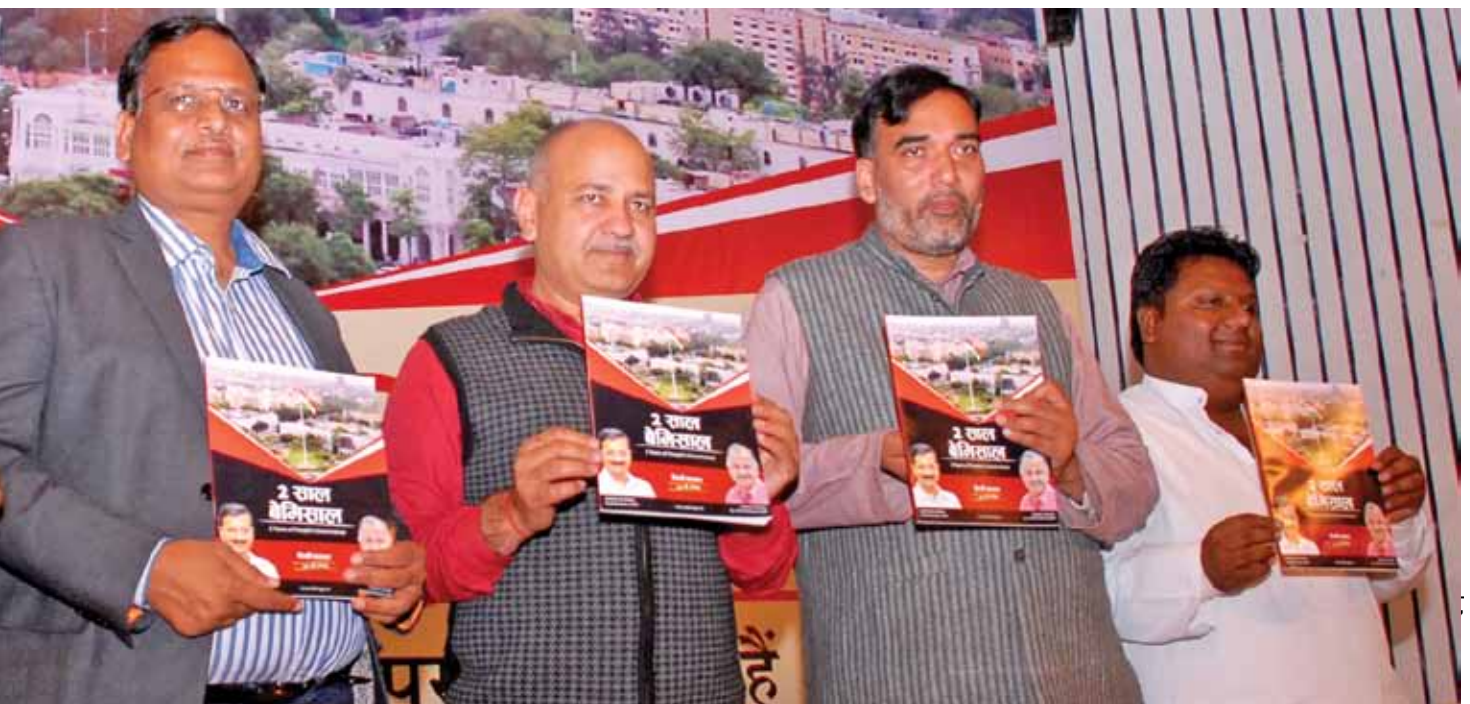
14 फरवरी 2017 को सरकार के दो साल का कार्यकाल पूरा होने पर दिल्ली सचिवालय में एक समारोह आयोजित हुआ। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तथा अन्य मंत्रियों ने सरकार की उपलब्धियाँ गिनाईं और अधूरे कामों को जल्द पूरा करने का संकल्प जताया। श्री सिसोदिया ने कहा कि वे रोज़ मोबाइल पर मेनीफ़ेस्टो चेक करते हैं ताकि पता रहे कि सरकार अपने वादे कहाँ तक पूरा कर पाई। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार एक सपने का नाम है जो आम आदमी की उम्मीदों की ताकत पर खड़ी है। उन्होंने शिक्षा तथा अन्य क्षेत्र में आये तमाम बदलावों का जिक्र किया। साथ ही बताया कि वाई-फाई सुविधा के लिए भी सरकार गंभीरता से कदम बढ़ा रही है।

इस मौके पर दिल्ली के जल मंत्री ने बताया कि ईमानदारी और जुनून से उनकी सरकार काम कर रही है। दिल्ली में जल संकट को हल किया गया है और यमुना सफाई को लेकर भी कई महात्वाकांक्षी परियोजनाएँ चल रही हैं। चार महीने में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का स्मारक बनना बड़ी उपलब्धि रही। श्रम मंत्री गोपाल राय ने कहा कि उनकी सरकार के कामकाज की खुशबू

पूरी दुनिया में फैल रही है। उन्होंने बताया कि निर्माण मजदूरों के हित में जैसे कदम दिल्ली सरकार ने उठाए हैं, वैसा शायद ही कहीं हुआ हो। देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों की याद में सरकार एक अनोखी डिजिटल डायरी बना रही है।

स्वास्थ्य एवं ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली की स्वास्थ्य तथा बिजली सेवाओं में आए बदलावों की चर्चा करने के साथ बताया कि जल्दी ही दिल्ली में 1000 मोहल्ला क्लीनिक और 100 आम आदमी कैंटीन खुल जाएँगी। वहीं खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने बताया कि अब गोदाम से राशन निकलते ही उपभोक्ता के मोबाइल पर मैसेज जाता है।

इस अवसर पर सभी मंत्रियों ने योजनाओं को कुशलतापूर्वक अमली जामा पहनाने के लिए सरकारी अधिकारियों की जमकर तारीफ की। इस मौके पर दो साल के कार्यकाल पर दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रचार निदेशालय की संकलित "वर्किंग रिपोर्ट" का विमोचन भी किया गया। ■



शिक्षा



बुनियादी ढाँचे का निर्माण

- 8000 नई कक्षाएँ (तकरीबन 200 स्कूलों के बराबर ढाँचागत निर्माण)।
- 21 नए स्कूल भवन।
- 54 स्कूलों में अत्याधुनिक सुविधाएँ।
- सभी कक्षाओं में ग्रीन बोर्ड।
- स्वच्छता के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल।
- लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग उपयोगी शौचालय।
- आर.ओ. तकनीक से शोधित पेयजल सुविधाएँ।
- सभी स्कूलों में सीसीटीवी सुरक्षा कैमरे।
- शिक्षकों के स्टाफ रूम का कार्यालय।
- स्कूल से आगे की पढ़ाई के लिए सरकारी की गारंटी पर 10 लाख तक का लोन।

अकादमिक उपलब्धियाँ

- चुनौती 2018:** सरकारी स्कूल के छात्रों में सीखने की कमियों को दूर करने के लिए अभियान।
- शिक्षक दिवस से बाल दिवस तक 'पढ़ने की शतप्रतिशत क्षमता' अभियान में एक लाख से अधिक बच्चों ने पढ़ना सीखा।

- पूरी दिल्ली में समुदायों, पार्कों, मैदानों में 1000 'रीडिंग मेले'।
- 500 स्कूलों में ग्रीष्मकालीन शिविर (समर कैम्प) का आयोजन।
- महानगर के सभी स्कूलों में एक साथ दो मेगा-पीटीएम आयोजित, मेगा-पीटीएम में भारी संख्या में अभिभावकों की सहभागिता।

प्राइवेट स्कूलों पर नकेल

- सरकार ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने पर रोक लगाई। इसके लिए सरकारी भूमि पर बने सभी निजी स्कूलों का ऑडिट किया गया और पहली बार स्कूलों ने अभिभावकों को जमा की गयी बढ़ी फीस लौटाई।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के लिए ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम लागू किया।

अंबेडकर विश्वविद्यालय का विस्तार

- कर्मपुरा में अंबेडकर विश्वविद्यालय का नया परिसर खोला गया। स्नातक स्तर पर चार पाठ्यक्रमों की शुरुआत, 2100 छात्रों को दो नए कैम्पसों में दाखिला दिया गया। वर्ष 2022 तक छात्रों की संख्या 10000 तक पहुंचने की संभावना है।

विस्तार योजना

- आईआईआईटी-डी के फेज-2 का निर्माण जून 2017 तक पूरा होने की संभावना है, जिससे छात्रों के दाखिले के लिए 1400 अतिरिक्त सीटें 3 उपलब्ध होंगी।
- नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया जा रहा है और छात्रों की संख्या 4000 से बढ़ाकर 10000 की जा रही है।
- सिंगापुर सरकार के सहयोग से स्थापित विश्व स्तरीय कौशल केंद्र में 2015-16 के दौरान नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। प्रवेश क्षमता 400 सीटों से बढ़कर 900 हो गई है।

स्वास्थ्य सेवाएँ



दिल्ली सरकार ने मुफ्त दवा,

मुफ्त जाँच का अपना वादा पूरा किया

- सरकार ने 36 मल्टीस्पेशलिटी अस्पतालों के साथ मजबूत स्वास्थ्य सेवा की ढांचागत संरचना तैयार की है। इनमें छह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, ब्लड बैंक और ब्लड स्टोरेज की सुविधाओं वाले 10 अस्पताल तथा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 69 प्राइवेट अस्पतालों में 731 निःशुल्क बिस्तर सहित 11,000 से अधिक बिस्तर शामिल हैं।
- दिल्ली में 242 ऐलोपैथिक डिस्पेंसरी, 107 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक (पायलट व नियमित), 23

पोलीक्लीनिक, 58 सीड प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केंद्र (पीयूएचसी), 39 आयुर्वेदिक, 19 यूनानी व 101 होम्योपैथिक डिस्पेंसरी, 43 मोबाइल क्लिनिक, 70 स्कूल हेल्थ क्लिनिक हैं।

- स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का काम 25000 से अधिक डॉक्टर और संबद्ध स्वास्थ्य सहायक कर रहे हैं।

नई पहल

- एमबीबीएस कोर्स में 100 सीटों की क्षमता के साथ नए मेडिकल कॉलेज, 'बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज, रोहिणी' में कामकाज शुरू।
- दिल्ली के 10 सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क मेडिकल और सीटी स्कैन।
- सभी मरीजों के लिए निःशुल्क दवाइयां और मेडिकल टेस्ट।
- दिल्ली के निवासियों के लिए युनिवर्सल हेल्थकेयर इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने की योजना। इस स्कीम का लक्ष्य डायग्नॉस्टिक, प्रोसीजर और सर्जरी सहित कैशलेस तरीके से अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा प्रदान करना है।
- दिल्ली सरकार द्वारा "होम टु हॉस्पिटल केयर" एंबुलेंस सर्विस स्कीम का शुभारंभ किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत कैट्स एंबुलेंस घर के दरवाजे पर सभी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी के लिए निःशुल्क एंबुलेंस सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।



बिजली



- पिछले दो वर्षों के दौरान बिजली की दरों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई।
- सरकार द्वारा मार्च 2015 से राजधानी दिल्ली के घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 400 यूनिट तक बिजली की खपत पर 50 फीसदी की सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
- बिजली कटौती की शिकायतों के निवारण के लिए 24 घंटे चलने वाले कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। डिसकॉम को यह सुनिश्चित करने को कहा गया

है कि अनावश्यक बिजली कटौती नहीं की जाए और यदि आवश्यक हो तो भी 1 घंटे से अधिक अवधि के लिए कटौती ना करें।

- बिजली विवाद समाधान स्कीम**—काफी समय से लंबित उपभोक्ता शिकायतों और विवादों को हल करने के लिए सरकार ने जनता के हित में बिजली विवाद समाधान स्कीम शुरू की हैं। इस योजना के माध्यम से लगभग 35,000 उपभोक्ता सीधे तौर पर लाभान्वित हुए हैं।
- ऊर्जा सक्षम एलईडी बल्ब**—उपभोक्ताओं को 93 रुपये प्रति बल्ब की दर से चार एलईडी बल्ब मुहैया करा, जा रहे हैं। लगभग 65 लाख एलईडी बल्ब उपभोक्ताओं को वितरित किए जा चुके हैं।
- लगभग 1-32 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट दिल्ली में लगाई गई हैं।
- सोलर रूफ टॉप पॉलिसी के तहत सरकारी भवन की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। दिल्ली में नेट मीटरिंग के तहत करीब 200 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं।
- सर्वश्रेष्ठ ट्रांसमिशन यूटिलिटी अवार्ड—दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड को बेहतर बिजली सेवा उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2016 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी अवार्ड से नवाजा गया।
- विद्युत उत्पादन क्षेत्र में दूसरा स्थान—राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 2016 के तहत दिल्ली सरकार की विद्युत उत्पादन कंपनी पीपीसीएल को वर्ष 2016 के लिए दूसरी सर्वश्रेष्ठ विद्युत उत्पादन कंपनी का पुरस्कार मिला।



जल आपूर्ति



दिल्ली सरकार ने 20,000 लीटर तक मुफ्त पानी देने का अपना वादा लगातार दूसरे साल भी पूरा किया।

- पानी के 12,56,883 घरेलू उपभोक्ता परिवारों ने 20,000 लीटर प्रति माह तक की निःशुल्क जल आपूर्ति का लाभ उठाया। इसके बावजूद दिल्ली जल बोर्ड का राजस्व बढ़ा। राजस्व संग्रह 2014-15 में रुपये 1219-49 करोड़ था जो 2015-16 में बढ़कर रुपये 1549-94 करोड़ हो गया। 2016-17 (28-12-16 तक) रुपये 869-13 करोड़ राजस्व के रूप में प्राप्त हुए।
- 01-04-2015 को सक्रिय उपभोक्ताओं की जो संख्या 19-20 लाख थी, वह बढ़कर 21-66 लाख हो गई है तथा इन सभी उपभोक्ताओं की त्रिमासिक बिलिंग सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- जल और सीवर विकास शुल्क जो रु. 494 प्रति वर्ग मीटर था, उसमें भारी कटौती करके रु. 100 प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है।
- 309 अनाधिकृत कालोनियों में नल-जल आपूर्ति कराई गई है, इस प्रकार कुल 1797 अनाधिकृत कालोनियों में से नल-जल आपूर्ति वाली कालोनियों की संख्या 1103 हो गई।

- शहर में पानी की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, गर्मी के मौसम में तकरीबन 900 एमजीडी पेयजल का अधिकतम उत्पादन हासिल किया गया है।
- जल अभाव वाले क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए, ट्यूब वेल, वॉटर एटीएम की स्थापना के साथ-साथ 700 टैंकों के मौजूदा बेड़े में स्टेनलेस स्टील के 250 नए पानी के टैंकर शामिल किए गए हैं।
- वेब आधारित ऑनलाइन टैंकर मॉनिटरिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाया गया है ताकि लोग अपने मोहल्लों में आने वाले टैंकों का और उनमें आने वाली पानी की मात्रा का पता लगा सकें।
- द्वारका और बवाना में क्रमशः 50 और 20 एमजीडी क्षमता के दो जल उपचार संयंत्र चालू किए गए हैं जिनसे लगभग 20 लाख लोगों को लाभ होगा।
- पूरी दिल्ली में कई नए भूमिगत जलाशयों और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों को चालू किया गया है जिनसे 25-30 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं।

सीवरेज

- 6 सीवरेज उपचार संयंत्रों को चालू करने से सीवरेज उपचार क्षमता बढ़कर 604 एमजीडी हो गई है।
- दिल्ली में 200 किलोमीटर ट्रंक सीवर नेटवर्क के साथ 7700 किलोमीटर का सीवर नेटवर्क है। 135 शहरी गांवों में से, 130 गांवों को सीवरेज सुविधा, प्रदान की गई है। इसके अलावा 189 ग्रामीण गांवों में से 45 गांवों में सीवरेज सुविधा, प्रदान करने का कार्य पूरा कर लिया गया है।
- दिल्ली गेट में 15 एमजीडी क्षमता का सीवरेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) और यमुना विहार में 25 एमजीडी क्षमता का सीवरेज उपचार संयंत्र चालू किया गया है।
- यमुना नदी जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए नए एसटीपी की स्थापना अत्याधुनिक तकनीक के साथ की जा रही है।
- 89 एमजीडी उपचारित पानी का इस्तेमाल सिंचाई, बागवानी के लिए और साथ ही विद्युत संयंत्रों में आपूर्ति के लिए भी किया जा रहा है।
- सीवरेज मास्टर प्लान 2031 का कार्य शुरू कर दिया गया है।

पर्यावरण

ऑड-ईवन स्कीम

- दिल्ली में भारी प्रदूषण और ट्रैफिक जाम को देखते हुए, दिल्ली सरकार ने 01 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक तथा 15 से 30 अप्रैल 2016 तक, दो बार 'ऑड-ईवन स्कीम' लागू की। इस स्कीम के अंतर्गत चार-पहिया निजी वाहनों को उनके सम-विषम (ऑड-ईवन) रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर, एक-एक दिन छोड़कर दिल्ली की सड़कों पर चलने की अनुमति थी। इस स्कीम को दुनिया भर से व्यापक सराहना मिली।

कार फ्री डे

- दिल्ली सरकार ने 22 अक्टूबर 2015 को पहली बार "कार-फ्री डे" घोषित किया। इस दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद एक साइकिल रैली की अगुवाई की जिसमें 1000 से अधिक साइकिल सवारों ने हिस्सा लिया। इसने लोगों को सार्वजनिक वाहनों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया। पहले 'कार फ्री डे' का दायरा लाल किले से भगवान दास रोड तक था।
- दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन सेवा के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए तीन महीनों तक अलग-अलग क्षेत्रों में 'कार-फ्री डे' का आयोजन किया। यह उन कई उपायों में से एक है जो शहर के वायु प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करेगा।

वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्य योजना

- सरकार ने दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को काबू में करने के लिए निम्नलिखित आपातकालीन कदम उठाए हैं—
- दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन (बीटीपीएस) की सभी इकाइयों को बंद किया गया।
- बीटीपीएस से फ्लाई-ऐश उठाने पर तत्काल रोक और फ्लाई ऐश स्टोरेज पर पानी का छिड़काव।
- सड़कों पर झाड़ू लगाने से पहले पानी का छिड़काव।
- अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली में सभी क्षमताओं के डीजल जेनसेट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है।
- पटाखों पर प्रतिबंध (धार्मिक समारोहों को छोड़कर)।

- परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने सीमाओं पर और दिल्ली के भीतर कारवाइयाँ तेज की है, जैसे ओवरलोडेड ट्रकों के प्रवेश पर रोक, ऐसे ट्रकों के प्रवेश पर रोक जिनका गंतव्य दिल्ली नहीं है, उन वाहनों के खिलाफ कारवाई जिनके पास वैध पीयूसीसी नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कारवाई। बिना ढके निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों के खिलाफ कारवाई।
- 7 नवंबर 2016 से 14 नवंबर 2016 तक दिल्ली में सभी निर्माण, तोड़फोड़ की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया।
- डीपीसीसी, एसडीएम और पुलिस के अधिकारियों के विशेष दल बनाकर कूड़ा, सूखी पत्तियाँ जलाने के खिलाफ कारवाई।
- कूड़ा, सूखी पत्तियाँ जलाने की कंप्यूटर ऐप्लिकेशन आधारित मॉनिटरिंग।
- सैनिटरी लैंडफिल साइटों में आग नियंत्रित करने के लिए सभी पालिका निकायों को निर्देश।

बैटरी चालित वाहनों को बढ़ावा

- गैर-प्रदूषणकारी ई-वाहनों को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से, सरकार ने दुपहिया वाहनों, चार-पहिया वाहनों और साथ ही ई-रिक्शा जैसे विभिन्न प्रकार के ई-वाहन खरीदने पर सब्सिडी स्कीम की घोषणा की है। परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पंजीकृत बैटरी चालित ई-रिक्शा मालिक को रु 30,000 की एकमुश्त सब्सिडी दी जाती है।

खुले में कचरा जलाने वालों पर कारवाई

- कचरा-अपशिष्ट पदार्थ, पत्तियाँ जलाने को रोकने के लिए, डीपीसीसी ने "डेल्टा पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी" के नाम से एक फेसबुक अकाउंट खोला है और साथ ही मोबाइल नंबर 9717593574 के साथ एक व्हाट्सऐप अकाउंट भी शुरू किया गया है।
- सूखी पत्तियाँ, कचरा, प्लास्टिक इत्यादि जलाने पर रोक लगाने में लापरवाही पर एस-ओ-(बागवानी) और सैनिटेशन इंस्पेक्टर को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ कारवाई की जाएगी।
- दिल्ली पार्कस् ऐंड गार्डन्स सोसायटी (डीपीजीएस) ठोस अपशिष्ट की डंपिंग से यमुना के बाढ़ के मैदानों की सफाई कर तथा यमुना फ्लड बैंकों को उनके मूल रूप में वापस लाकर माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित करती है।

परिवहन

बस डिपो का निर्माण

- दिल्ली सरकार अपने डीटीसी बेड़े को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है जो हमारे सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क का आधार है। बस डिपो के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध न हो पाने के कारण, बसों की संख्या में इजाफा नहीं किया जा रहा था। सरकार ने इस मामले को प्राथमिकता पर लिया और अब तकरीबन 415 करोड़ रुपये की लागत से 11 बस डिपो बनकर तैयार होने के विभिन्न चरणों में हैं। इन प्रयासों के कारण सरकार अब लगभग 3000 नई बसों के टेंडर जारी करने की ओर अग्रसर है।

क्लस्टर बसें

- असुरक्षित मानी जाने वाली ब्लू लाइन बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का काम पूरा हो चुका है। उनके स्थान पर सरकार ने क्लस्टर बस सिस्टम के अंतर्गत नई बसों की संख्या में वृद्धि करने की शुरुआत कर दी है। इन नई योजना के तहत 11,000 बसों के समेकित बेड़े में से, डीटीसी प्रत्येक क्लस्टर रूट में 50 फीसदी बसों का संचालन करेगा और बाकियों का संचालन निजी कंपनियों द्वारा किया जाएगा।
- पिछले वर्ष के दौरान क्लस्टर बस स्कीम के तहत 200 से अधिक बसों को शामिल किया गया जिससे इस स्कीम के अंतर्गत आने वाली बसों की कुल संख्या 1700 हो गई है। मार्च 2017 तक इस स्कीम के अंतर्गत और 225 और बसों को शामिल किया जाएगा।

महिला सुरक्षा

- महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए डीटीसी बसों में (शाम और रात की शिफ्ट में) 1269 होमगार्ड, 1818 सिविल डिफेंस वॉलंटियर और 170 अतिरिक्त स्टाफ को 'मार्शल' के रूप में तैनात किया गया है।
- स्टेज कैरिज बसों और मेट्रो फीडर बसों में महिलाओं के लिए 25 फीसदी सीटें आरक्षित की गई हैं।
- 26 रूटों पर व्यस्ततम समय के दौरान लेडीज स्पेशल बसें चलाई जा रही हैं।
- डीटीसी बसों में सीसीटीवी कैमरा: 200 लो फ्लोर बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रारंभिक परियोजना पूरी हो गई

है। सरकार ने सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया है।

ऑटो परमिट

- दिल्ली में ऑटो रिक्शा की, यात्रियों के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी में प्रमुख भूमिका हैं। सरकार ने एलओआई स्कीम स्वीकृत की है और इस वर्ष 10,000 नए ऑटो परमिट जारी किए गये हैं।

दिल्ली मेट्रो फेज-4

- डीएमआरसी का मौजूदा नेटवर्क 189 किलोमीटर का है। 140 किलोमीटर के लिए डीएमआरसी के तीसरे चरण का कार्य 11-04-2011 को स्वीकृत हो गया था। यह कार्य जून 2017 तक पूरा होने की संभावना है। इसके बाद मेट्रो रेल का कुल नेटवर्क 330 किलोमीटर हो जाएगा। सरकार ने 116 किलोमीटर के आठ कॉरिडोर वाले मेट्रो फेज-4 को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दी है। फेज-4 का कार्य दिसंबर 2021 तक पूरा होने की संभावना है।

इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग सिस्टम

- दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुचारु, सुगम और पारदर्शी बनाने के प्रयास के तहत स्टेज कैरिज बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनों की शुरुआत की है। सभी क्लस्टर बसों में अब इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनें हैं।

ऑनलाइन नागरिक परिवहन सेवाएँ

- ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अपॉइंटमेंट और फीस भरने की ऑनलाइन सुविधा पहले ही शुरू की जा चुकी है ताकि प्रक्रिया सुगम हो और समय की बचत भी हो सके। दिल्ली में वाहन सॉफ्टवेयर को कार्यान्वित कर दिया गया है जिसमें डीलर की ओर से निजी वाहनों का पंजीकरण, आरसी जारी किया जाना, डुप्लीकेट आरसी, अस्थायी पंजीकरण, स्वामित्व का हस्तांतरण आदि सेवा, शामिल है।

“पूछो” ऐप

- सरकार ने शहर में टैक्सी और ऑटो-रिक्शा सेवाओं को सुगम बनाने के लिए “पूछो” ऐप लॉन्च किया है। यह सेवा उन ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स को एक कॉमन सर्वर से जुड़ने में सक्षम बनाएगी जिनके वाहनों में जीपीएस लगा हुआ है। उसके बाद यात्री अपने स्मार्टफोन के जरिए टैक्सी या ऑटोरिक्शा घर बैठे बुक कर सकेंगे। ऑटो फाइंडर ऑप्शन के साथ-साथ, यात्रियों की सुविधा के लिए यह ऐप किराया भी बताएगा और यातायात की लाइव अपडेट भी देगा।

श्रम

श्रमिक विकास मिशन का गठन

- अन्तर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मई 2015 के अवसर पर श्रमिक विकास मिशन का शुभारम्भ किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य न्यूनतम मजदूरी को सही रूप से लागू करना और निर्माण व अन्य श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं के रूप में मिलने वाली आर्थिक सहायता में वृद्धि करना है।

श्रमिकों के लिए हैल्प लाइन

- निर्माण श्रमिकों के लिए एक हैल्पलाइन नं. 155214 शुरू किया गया है। इस श्रमिक हैल्प लाइन पर पिछले दो सालों में 25 हजार 5 सौ 63 शिकायतें/जानकारी संबंधित कॉल मिली और सभी का संतोषजनक ढंग से निपटारा किया गया।

श्रमिकों को सहायता

- पिछले 2 सालों में श्रम विभाग द्वारा विभिन्न श्रम कानूनों के तहत 58-08 करोड़ रुपये की धनराशि की सहायता 13,831 मजदूरों को दिया गया है।

बाल मजदूर मुक्ति अभियान

- पिछले दो सालों में जिला श्रम विभाग की टास्क फोर्स द्वारा 150 बार औचक निरीक्षण कर 1114 बाल मजदूरों को मुक्त कराया साथ-ही-साथ 123 कारखानों/संस्थाओं को सील कर दिया गया जहाँ इन बच्चों से कार्य कराया जा रहा था और इनसे 15 लाख 40 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर वसूल किया गया।

श्रमजीवी पत्रकारों का हित

- शीतकालीन सत्र 2015 के दौरान विधानसभा में "श्रमजीवी पत्रकारों और अन्य समाचार पत्र कर्मचारियों के विविध प्रावधान संशोधन विधेयक" पारित किया गया। विधेयक में श्रमजीवी पत्रकारों और अन्य समाचार पत्र कर्मचारियों का उनके वैध मजदूरी सहित पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित करने का प्रावधान है।

- ऑनलाइन सेवाएँ-विभाग द्वारा 11 सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाइन किया जा रहा है जिसमें से दो सेवाओं शॉप एंड इस्टेबलिशमेंट एक्ट के अन्तर्गत लाइसेंस और फैक्ट्री भवन निर्माण योजना लाइसेंस को ऑनलाइन कर दिया गया है।
- ऑनलाइन सेवा, प्रारम्भ करने के बाद भवन निर्माण योजना की स्वीकृति में मात्र तीन दिन का समय लगता है जबकि पहले यह स्वीकृति 3-4 महीने में दी जाती थी। इसी प्रकार फैक्ट्री लाइसेंस जारी करने का समय भी 3 महीने के स्थान पर सिर्फ एक सप्ताह हो जाएगा।

श्रमिक कल्याण बोर्ड

- बोर्ड की 18 योजनाओं द्वारा निर्माण श्रमिकों को सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से 7 योजनाओं का लाभ पंजीकरण की तिथि से ही मिलना प्रारम्भ हो गया है। ये योजनाएँ हैं 1) प्रसुति सहायता 2) विकलांगता सहायता 3) एक्स गेसिया 4) अंतिम दाह संस्कर सहायता 5) आकस्मिक मृत्यु सहायता 6) कक्षा 1 से 12 तक शिक्षा के लिए सहायता 7) गर्भपात होने की स्थिति में दी जाने वाली सहायता।
 - बोर्ड में कुल 4 लाख 11 हजार 5 सौ 76 (411576) निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चुका है। इसमें 1,68,044 लाइव सदस्य हैं।
 - बोर्ड द्वारा अब तक कुल 2200 करोड़ रुपये सेस एवं ब्याज के रूप में संग्रहित किए गए।
 - भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों का बीमा।
 - निर्माण मजदूरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना जल्द लाया जाएगा। इसके लिए बीमा कंपनियों से बातचीत की जा रही है।
 - यह भी फैसला लिया गया कि सभी तरह की कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित पैसा श्रमिकों के खाते में सीधे जाए।
- आगे मजदूरों के पंजीकरण के लिए बैंक अकाउंट जरूरी किया जाएगा।



प्रशासनिक सुधार



- विभिन्न विभागों, स्थानीय निकायों और दूसरे सरकारी संगठनों की ओर से मांगे जाने वाले 200 श्रेणियों के हलफनामों की समाप्ति। अब इसके स्थान पर आत्म-प्रमाणीकरण को अपना लिया गया है। मार्च 2015 में सरकार के गठन के एक महीने के भीतर ही कैबिनेट ने इस बारे में फैसला लिया था। इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया।
- तत्काल विवाह पंजीकरण शुल्क को 10,000 रुपये से घटाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। यह तत्काल आधार पर अपने विवाह को पंजीकृत करवाने वाले जोड़ों के लिए एक बड़ी राहत है। 20 जनवरी 2017 को इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की गई।
- एक आधुनिक, व्यापक और पारदर्शी भूमि रिकार्ड प्रबंधन प्रणाली को विकसित करने के लिए भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण परियोजना का कार्यान्वयन किया गया। राजस्व विभाग के इंद्रप्रस्थ भू-लेख (दिल्ली भूमि रिकार्ड सूचना) ने नागरिकों की सुविधा के लिए डिजिटल हस्ताक्षर वाले आरओआर (रिकार्ड का अधिकार) जारी करने की सुविधा उपलब्ध करवाई।
- 186 गांवों के 33458 खातों की जमीन के भूमि रिकार्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध। दिल्ली सरकार के सभी जिला कार्यालयों में 1 नवंबर 2016 के बाद डिजिटल

रिकार्ड वाले खातों के लिए केवल डिजिटल हस्ताक्षर वाले आरओआर ही जारी किए जा रहे हैं।

- संबंधित जिला कार्यालयों के नागरिक सेवा केन्द्रों से आरओआर प्राप्त किए जा सकते हैं या उन्हें वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। यह सेवा चौबीस घंटे उपलब्ध है।

स्टाम्प और पंजीकरण

- जनवरी 2016 से शेषरों पर स्टाम्प शुल्क का संग्रह ऑनलाइन माध्यम से शुरू कर दिया गया है।
- मार्च 2016 से उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों में होने वाले संपत्ति के पंजीकरण का कार्य ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके साथ ही नागरिकों को संपत्ति के विवरण की जानकारी लेने के लिए ई-सर्च की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है।
- ई-जिला परियोजना के लिए नागरिक कॉल सेंटर।
- राजस्व विभाग के मुख्यालय में ई-जिला परियोजना के तहत नागरिकों के प्रश्नों, शिकायतों, सुझावों की प्रभावी निगरानी के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना।
- यह कॉल सेंटर सुबह 09.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक रविवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में कार्य करता है। इस कॉल सेंटर में ई-डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध 33 सेवाओं के संबंध में सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं।



सार्वजनिक वितरण प्रणाली



- दिल्ली सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की लगभग 2500 अधिकृत राशन की दुकानों के माध्यम से लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित कर रही है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने, खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और वितरण श्रृंखला को मजबूत करने के लिए सभी लाभार्थियों को शत प्रतिशत आधार कार्ड से जोड़ा है। दिल्ली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कुल 19.46 लाख राशन कार्ड चिन्हित हैं। दिल्ली में अब तक लगभग 72 लाख लोग इस श्रृंखला से जुड़ चुके हैं।
- दिल्ली में 40 एफपीएस (राशन की दुकान) पर पायलट परियोजना के तहत बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के बाद राशन जारी किया जा रहा है। सभी एफपीएस (पीओएस) को बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण की व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है, जिससे राशन की कालाबाजारी को रोका जा सकता है।

राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी

- राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को प्रायोगिक आधार पर दिल्ली छावनी विधान सभा क्षेत्र में लागू किया गया है। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के तहत एक निर्वाचन

क्षेत्र में स्थित किसी भी राशन दुकान से लाभार्थी राशन प्राप्त कर सकता है।

राशन आवाजाही की निगरानी

- भारतीय खाद्य निगम से दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को खाद्यान्न की आपूर्ति होती है। इसकी निगरानी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है। कार्ड धारकों को उनका राशन सुचारु रूप से मिलना सुनिश्चित कराने के लिए ऑनलाइन प्रणाली से राशन कार्ड धारकों और राशन वितरकों को एक साथ ही राशन वितरण के बारे में जानकारी का एसएमएस मिल जाता है। इससे राशन की कालाबाजारी पर रोकथाम में मदद मिलती है।

नया खाद्य सुरक्षा पोर्टल

- दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुगम बनाने के उद्देश्य से नागरिकों के लिए एक पोर्टल विकसित किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए इस नए पोर्टल के माध्यम



से लाभार्थियों को जोड़ा जा रहा है। राशन कार्ड धारकों को संबंधित सेवाओं की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है।

- राशन हेल्पलाइन/कॉल सेंटर नंबर 1967
- राशन वितरण में समय की बाध्यता समाप्त।
- दिल्ली सरकार ने विभाग के निरीक्षकों द्वारा संचालित वितरण प्रारंभ प्रणाली को खत्म करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राशन वितरण का कार्य अब हर महीने के पहले दिन शुरू होता है और राशन कार्ड धारक महीने भर राशन दुकानों से राशन प्राप्त कर सकते हैं। नई प्रणाली से राशन कार्ड धारकों और एफपीएस लाइसेंसधारियों को बड़ी राहत मिली है।

मोहल्ला क्लीनिक के मुरीद हुए कोफ़ी अन्नान

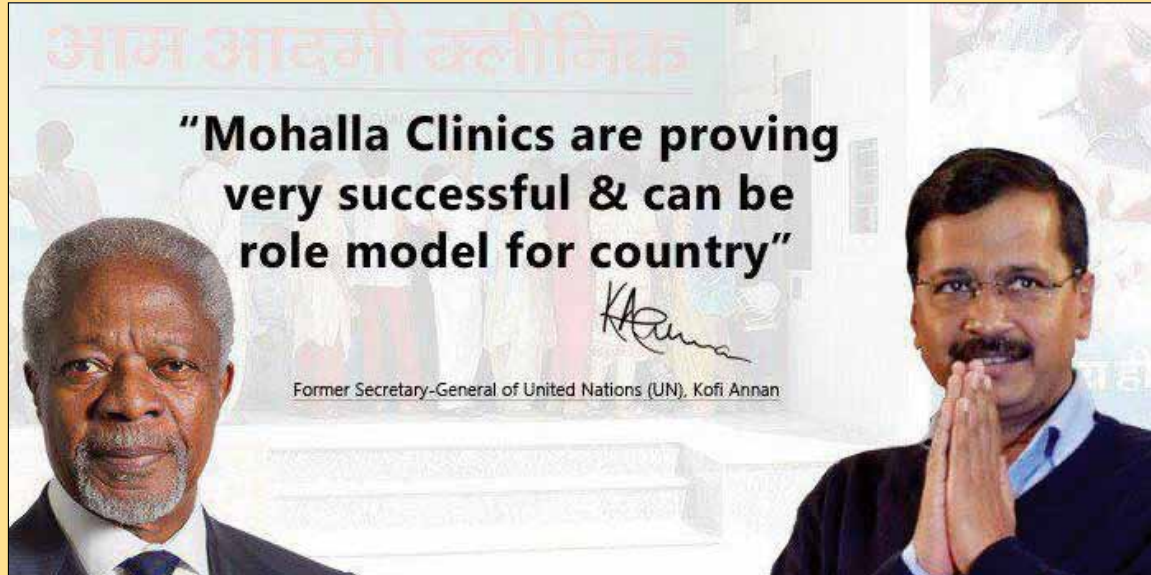
दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लीनिक की खुशबू पूरी दुनिया में फैल रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफ़ी अन्नान ने इस प्रयास को बेहतरीन बताते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है।

अन्नान ने कहा है कि जिस प्रकार मोहल्ला क्लीनिक में लोगों को सुविधा मिल रही है, वह एक बेहतर कॉस्ट इफेक्टिव शुरुआत है, जिसमें दिल्ली की आबादी को प्राइमरी हेल्थकेयर बिना किसी खर्च के मिल रहा है। उन्होंने सुझाव के तौर पर कहा कि सरकार को अपने

25 जनवरी 2017 को लिखे इस पत्र में कोफ़ी अन्नान ने मोहल्ला क्लीनिक को प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक दिल्ली ही नहीं पूरे भारत के हेल्थ सिस्टम में सुधार के लिए एक बेहतर मॉडल बन सकता है, दिल्ली सरकार के इस मॉडल को पूरे देश में अपनाने की जरूरत है।

अन्नान ने मोहल्ला क्लीनिक के साथ प्राथमिक चिकित्सा के लिए कई सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने मोहल्ला क्लीनिक को पैसों की तंगी से जूझ रहे गरीब तबके के लिए शानदार कदम बताया।

अन्नान ने पत्र में लिखा है—‘हमें पता है दिल्ली में आपकी सरकार यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अपना रही है। आपका एडमिनिस्ट्रेशन इस दिशा में एक साथ कई काम कर रहा है, जिसमें फ्री प्राइमरी हेल्थ केयर के रूप में आपका मोहल्ला क्लीनिक काफी सफल साबित हो रहा है।’ उन्होंने उम्मीद जताई है कि दिल्ली सरकार इसे और आगे लेकर जाएगी और इसकी सफलता को देखते हुए भारत के दूसरे राज्य भी इसे अपना सकते हैं। कोफ़ी



मोहल्ला क्लीनिक का मूल्यांकन करते रहना चाहिए, ताकि इस प्रोग्राम का प्रभाव बना रहे। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार को डॉक्यूमेंट्स तैयार करना चाहिए ताकि भारत के दूसरे राज्य भी इसे अपना सकें।

दिल्ली में अब तक 107 मोहल्ला क्लीनिक खोले गए हैं। इन चिकित्सा केंद्रों में दवा से लेकर परामर्श तक सब कुछ मुफ्त है। इससे पहले अमेरिका के 'वॉशिंगटन पोस्ट' और फ्रांस के मेडिकल जर्नल 'लैनसेट' ने भी मोहल्ला क्लीनिक के लिए दिल्ली सरकार की तारीफ की थी।

संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफ़ी अन्नान फिलहाल नेलसन मंडेला शांति, न्याय और मानवाधिकार के लिए दुनिया भर में सक्रिय हैं। ■

संक्षेप में... संक्षेप में... संक्षेप में...

1 किमी दायरे के हर बच्चे का एडमिशन

नर्सरी एडमिशन को लेकर हर साल होने वाली अफरातफरी को ख़त्म करने के लिए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाया है। अब सरकारी जमीन पर बने स्कूलों को वह शर्त हर हाल में माननी होगी जिसमें कहा गया है कि वे आसपास रहने वाले बच्चों को एडमिशन से मना नहीं करेंगे।

दिल्ली में करीब 400 स्कूल ऐसे हैं, जहां पर नर्सरी एडमिशन के लिए सबसे ज्यादा मारामारी देखने को मिलती है। इनमें से 285 ऐसे स्कूल हैं, जो डीडीए की जमीन पर बने हुए हैं। दिल्ली सरकार ने डीडीए अलॉटमेंट लेटर्स की शर्तों के सहारे ही इस बार एडमिशन की राह आसान बनाने की तैयारी की है। दरअसल जमीन आवंटन की शर्तों में है कि स्कूल आसपास रहने वाले बच्चों को एडमिशन से मना नहीं कर सकते। अलॉटमेंट लेटर्स में नेबरहुड कान्सेप्ट को फॉलो करने की बात है। दिल्ली सरकार अब इसी शर्त को सख्ती से लागू कराएगी। ऐसा होने पर स्कूल से 0-1 किमी की दूरी पर रहने वाले हर बच्चे का एडमिशन करीब-करीब निश्चित हो जाएगा।

जनता संतुष्ट तो ठेकेदार को पेमेंट

गली-मोहल्ले में होने वाले विकास कार्यों की क्वालिटी से जब तक वहां के लोग संतुष्ट न हों, तब तक ठेकेदार का पेमेंट न किया जाए। इस तरह का प्रयोग दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी विधानसभा पटपड़गंज में किया है। मनीष सिसोदिया ने पटपड़गंज के वार्ड नंबर 217 और 218 के कुछ मोहल्लों में हुए 15 विकास कार्यों का निरीक्षण किया। लोगों से काम की क्वालिटी के बारे में पूछा। जहाँ लोगों ने संतुष्टि जाहिर की, वहाँ पर ठेकेदार को पेमेंट के निर्देश दिए। एक जगह लोग काम से संतुष्ट नहीं थे, वहाँ ठेकेदार को पेमेंट रोकने को भी कहा।

उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने निरीक्षण दौरे का एक वीडियो अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करके लिखा कि वे विधायक फंड से होने वाले हर एक काम की जानकारी काम शुरू होते ही पर्चे के माध्यम से उस गली में बँटवा देते हैं। पर्चे में काम का पूरा विवरण, ठेकेदार, इंजीनियर आदि का फोन नंबर और लागत आदि सब लिखा रहता है। इसका असर ये हुआ है कि लोगों ने सामने खड़े होकर सड़कें बनवाई और ठेकेदार को वैसा ही काम करने पर मजबूर किया है जैसा पर्चे में लिखा होता है। ठेकेदार को पेमेंट तभी दिया जाता है जब लोगों की तरफ से उन्हें कार्यसंतुष्टि का लिखित पत्र मिल जाता है।

जलबोर्ड ने निकाले रिकॉर्ड बिल

इतिहास में पहली बार दिल्ली जल बोर्ड ने 19 लाख 50 हजार बिल निकाले। यह कुल बिलों का 92 फीसदी है जो कि एक रिकॉर्ड है।

साल भर पहले करीब 14 लाख बिल निकलते थे। इसमें बोर्ड की एम सेवा का बड़ा योगदान है। अब मीटर रीडर की जरूरत नहीं रह गई है। दिल्ली के जल मंत्री ने जल बोर्ड के कुछ अहम फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि बोर्ड ने कमर्शियल कनेक्शन के इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्ज खत्म कर दिया है। अब कनेक्शन के लिए फिक्स रेट लिए जाएँगे। 50 वर्गमीटर से कम जगह के लिए 45000 और 50 वर्गमीटर से बड़ी जगह के लिए 100000 रुपये लिए जाएँगे। इसके अलावा जलबोर्ड के सामुदायिक भवनों का इस्तेमाल आम नागरिक भी कर सकेंगे।

अवैध टैक्सियों पर कार्रवाई

दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने अवैध रूप से चलने वाली ऐप बेस्ड टैक्सियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की है। इस साल जनवरी से अक्टूबर तक 8,291 टैक्सियों के चालान किए गए और 1,873 टैक्सियां जब्त की गईं। इनमें ओला-उबर की कैब भी शामिल हैं। सितंबर-अक्टूबर में इस मुहिम में तेजी लाते हुए एनफोर्समेंट विंग ने दिल्ली में कई जगह टीमें लगाई और ज्यादा गाड़ियां जब्त की ऑटो-टैक्सी यूनियनों की मांग रही है कि ऐप बेस्ड टैक्सियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। यूनियन का कहना है कि यूपी, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में रजिस्टर्ड गाड़ियां दिल्ली के लोकल रूट्स पर चल रही हैं। इससे दिल्ली में रजिस्टर्ड ऑटो-टैक्सियों का बिजनेस बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इसी के साथ अवैध रूप से चलने वाले ई-रिक्शा के भी काफी चालान किए गए। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के भी काफी रिक्शा चल रहे थे। कुछ के पास लाइसेंस तक नहीं था।

शुरू हुआ मुकुंदपुर फ्लाईओवर

मुकुंदपुर चौक पर 6 लेन फ्लाईओवर शुरू हो गया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसका उद्घाटन किया। इस फ्लाईओवर के बनने के बाद विकासपुरी से वजीराबाद का करीब 22.5 किमी का सफर आसान हो गया। मुकुंदपुर चौक पर 6 लेन फ्लाईओवर निर्माण के लिए 62 करोड़ का बजट तय किया गया था, लेकिन यह करीब 50 करोड़ रुपये में बनकर तैयार हो गया है। 900 मीटर लंबे इस फ्लाईओवर को बनाने में करीब तीन साल का समय लगा। नवंबर 2013 में यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और नवंबर 2016 में यह फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया है। 3-3 लेन के रोड बनाए गए हैं। साथ ही साइकल ट्रैक और फुटपाथ भी बनाया गया है। एनएच-1 से गुजरने वालों को इस फ्लाईओवर से काफी फायदा होगा। प्रदूषण में भी कमी होगी और लोगों का समय भी बचेगा। इस फ्लाओवर से हर रोज डेढ़ लाख से ज्यादा वाहनों के गुजरने की उम्मीद है। ट्रैफिक जाम से भी छुटकारा मिलेगा और लोगों का बहुत समय बचेगा। फ्लाईओवर के दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट भी बनाई गई है। ■



ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਛਤਰਸਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਫਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇਕਰ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ—

ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ! ਇੰਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ!!

ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਤਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ। ਇਸੇ ਦਿਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਿਆ।

ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਦਲ ਦਿਤੀ।

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏ, ਖੱਟੇ-ਮਿੱਠੇ, ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਬਡੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ, ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਈ ਸਾਥੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਚ।

ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ, ਸੰਪਤੀ, ਸੜਕਾਂ, ਫਲਾਈਓਵਰ, ਏਅਰਪੋਰਟ, ਪਹਾੜ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਜਨਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿਤੀ ਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਤਮੰਦ ਬਣਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਨੀ-ਫਲਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਭਵਿਖ ਦੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਕਈ ਗੁਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਲੋਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਦੋਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਨਜੀਓ ਅਤੇ

ਐਕਸਪਰਟ ਇਸ ਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਦਸ-ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦੇਵੋ। ਅਸੀਂ ਸੋ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਜਟ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਭ ਪਾਸੇ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏ, ਖੱਟੇ-ਮਿੱਠੇ, ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਬਡੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।



ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੋਸਤੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਟਾਯਲੇਟ ਹੋਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਲਗ ਟਾਯਲੇਟ ਹੋਣ। ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬੇਹਤਰ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਲਾ ਇਕ-ਇਕ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਡੇਢ-ਦੋ ਸੌ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਣੇ।

ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐਮ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਣ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪੁੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਤਾ। ਮੈਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ

ਜਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੋਸਤੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ।

ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਫਟ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਗੰਦੀ ਮਛਲੀ ਪੂਰੇ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਦੀਆਂ

ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਇੰਟਰੇਸਟ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ





ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਫੀਸ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗੀ ਹੈ।

ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਘਿਨੋਣਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਪੂਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿੱਕ ਆ ਗਈ, ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਮਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਲੰਦਨ, ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਪਤਰਕਾਰ ਦੇਖਣ ਆਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਐਕਸਪਰਟ ਆਏ। ਅਲਟ੍ਰਾ ਮਾਡਰਨ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ, ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫਤ, ਜਾਂਚ ਮੁਫਤ। ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਹਨ। 122 ਪਾਲੀਕਲੀਨਿਕ ਬਣਨਗੇ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ। ਉਥੇ ਹੱਡੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਮਾਹਿਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਐਕਸਰੇ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਿਅਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ, ਟੈਸਟ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿਤੇ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਜਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੋਸਤੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਠਾਨ ਲੈਣ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਣਨਗੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਗੇ, ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਕ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਠਾਨ ਲਵੇ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ।

ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ

ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ।

“ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ !” ■



ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਚੈਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ - ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ

14 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕਤਰੇਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਪਮੁਖਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਤਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੋਦਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਚੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸੁਫਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਏ.ਪੀ.ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦਾ ਸਮਾਰਕ ਬਣਨਾ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧ ਰਹੀ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ।

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਵੈਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਡਾਇਰੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੋਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 1000 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ 100 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੈਂਟੀਨ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਉਧਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੋਦਾਮ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲਯ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਕਿੰਗ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਮੋਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ■



ਸਿੱਖਿਆ



ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

- 8000 ਨਵੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ (ਤਕਰੀਬਨ 200 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਰਮਾਣ)
- 21 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਭਵਨ
- 54 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ
- ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਨ ਬੋਰਡ
- ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
- ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਉਪਯੋਗੀ ਸ਼ੋਚਾਲਯ
- ਆਰ.ਓ. ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸ਼ੋਧਿਤ ਪੇਅਜਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ
- ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰੇ
- ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਰੂਮ ਦਾ ਕਾਇਮਾਕਲਪ
- ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ 10 ਲਖ ਤਕ ਦਾ ਲੋਨ।

ਅਕਾਦਮਿਕ ਉਪਲਬਧੀਆਂ

- ਚੁਣੌਤੀ 2018 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ

- ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਤਕ 'ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਰਥਾ' ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਇਕ ਲਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖਿਆ
- ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਮੂਦਾਇਆਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ 1000 'ਚੀਡਿੰਗ ਮੇਲੇ'
- 500 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਸਮਕਾਲੀਨ ਕੈਂਪ (ਸਮਰ ਕੈਂਪ) ਦਾ ਆਯੋਜਨ
- ਮਹਾਂਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਮੇਗਾ-ਪੀਟੀਐਮ ਆਯੋਜਿਤ, ਮੇਗਾ-ਪੀਟੀਐਮ ਨੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ

- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਨਮੰਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
- ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।

ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ

- ਕਰਮਪੁਰਾ ਵਿਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਰਿਸਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਸਨਾਤਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਾਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, 2100 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10000 ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
- ਆਈਆਈਟੀ-ਡੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-2 ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜੂਨ 2017 ਤਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਲਈ 1400 ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ 3 ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10000 ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ 2015-16 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਮਰਥਾ 400 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 900 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ



ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਦਵਾ, ਮੁਫਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ

- ਸਰਕਾਰ ਨੇ 36 ਮਲਟੀਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਵਾਸਥ ਸੇਵਾ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੰਰਚਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਛੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਬਲਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲੇ 10 ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲਈ 69 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ 731 ਮੁਫਤ ਬਿਸਤਰ ਸਮੇਤ 11,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਸਤਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 242 ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, 107 ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, (ਪਾਯਲਟ ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ), 23

ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕ 58 ਸੀਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ (ਪੀਯੂਐਚਸੀ), 39 ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ 19 ਯੂਨਾਨੀ ਤੇ 101 ਹੋਮੀਓਪੈਥਿਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 43 ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ, 70 ਸਕੂਲ ਹੈਲਥ ਕਲੀਨਿਕ ਹਨ।

- ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 25000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ

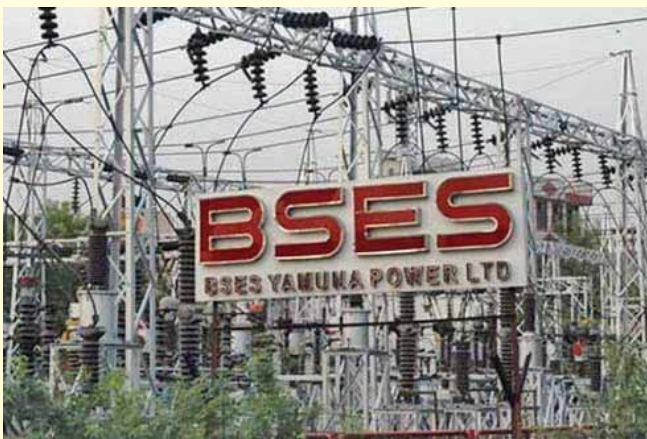
- ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕੋਰਸ ਵਿਚ 100 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, 'ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਰੋਹਿਣੀ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ।
- ਦਿੱਲੀ ਦੇ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ।
- ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ।
- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥਕੋਅਰ ਇੰਸ਼ੂਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਡਾਯਗਨਾਸਟਿਕ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਸਮੇਤ ਕੈਸਲੇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ “ਹੋਮ ਟੂ ਹਾਸਪੀਟਲ ਕੇਯਰ” ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸ਼ੁਭਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਟਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।



ਬਿਜਲੀ



- ▶ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
- ▶ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਚ 2015 ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 400 ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ▶ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ
- ▶ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲ ਸੇਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਸਕਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ



ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜੇਕਰ

- ▶ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ।
- ▶ ਬਿਜਲੀ ਵਿਵਾਦ ਹਲ ਸਕੀਮ-ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਵਾਦ ਹਲ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 35,000 ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਭਵੰਦ ਹੋਏ ਹਨ।
- ▶ ਊਰਜਾ ਸਮਰਥ ਐਲਈਡੀ ਬਲਬ-ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 93 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਲਬ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਚਾਰ ਐਲਈਡੀ ਬਲਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 65 ਲਖ ਐਲਈਡੀ ਬਲਬ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ।
- ▶ ਲਗਭਗ 1-32 ਲਖ ਐਲਈਡੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- ▶ ਸੋਲਰ ਰੂਫ ਟਾਪ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸੰਯੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨੇਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 200 ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸੰਯੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ▶ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਐਵਾਰਡ-ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਭਾਗ ਦਾ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
- ▶ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸੰਰਖਸ਼ਣ 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀ ਪੀਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਲਈ ਦੂਜਾ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।



ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ



ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20000 ਲੀਟਰ ਤਕ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ

- ਪਾਣੀ ਦੇ 12,56,883 ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ 20,000 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦੇ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰਾਜਸਵ ਵਧਿਆ। ਰਾਜਸਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 2014-16 ਵਿਚ ਰੁਪੈ 1219-49 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ 2015-16 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ ਰੁਪੈ 1549-94 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। 2016-17 (28-12-16 ਤਕ) ਰੁਪੈ 869-13 ਕਰੋੜ ਰਾਜਸਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
- 01-04-2015 ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗਿਣਤੀ 19-20 ਲਖ ਸੀ, ਉਹ ਵਧ ਕੇ 21-66 ਲਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਮਾਹੇ ਬਿਲਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਲਕ ਜੋ ਰੁ.-494 ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਰੁ.-100 ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- 309 ਅਣਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਲ-ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਲ 1797 ਅਣਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਲ-ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1103 ਹੋ ਗਈ।

- ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 900 ਐਮਜੀਡੀ ਪੈ ਅਜਲ ਦਾ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹਾਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਘਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟਯੂਬਵੈਲ, ਵਾਟਰ ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 700 ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇੜੇ ਵਿਚ ਸਟੇਨਲੇਸ ਸਟੀਲ ਦੇ 250 ਨਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਵੇਬ ਆਧਾਰਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਂਕਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਣ।
- ਦਵਾਰਕਾ ਅਤੇ ਬਵਾਨਾ ਵਿਚ ਲੜੀਵਾਰ 50 ਅਤੇ 20 ਐਮਜੀਡੀ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਦੋ ਜਲ ਉਪਚਾਰ ਸੰਯੰਤਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਲਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਜਮੀਨਦੇਜ਼ ਜਲਾਸ਼ਯਾਂ ਅਤੇ ਬੁਸਟਰ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 25-30 ਲਖ ਲੋਕ ਲਾਭਵੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੀਵਰੇਜ

- 6 ਸੀਵਰੇਜ ਉਪਚਾਰ ਸੰਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਉਪਚਾਰ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾ ਕੇ 604 ਐਮਜੀਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
- ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟ੍ਰੰਕ ਸੀਵਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ 7700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸੀਵਰ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। 135 ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 130 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਸੁਵਿਧਾ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, 189 ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 45 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸੁਵਿਧਾ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਵਿਚ 15 ਐਮਜੀਡੀ ਸਮਰਥਾ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਉਪਚਾਰ ਸੰਯੰਤਰ (ਐਸਟੀਪੀ) ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ 25 ਐਮਜੀਡੀ ਸਮਰਥਾ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਉਪਚਾਰ ਸੰਯੰਤਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਐਸਟੀਪੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਧਿਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- 89 ਐਮਜੀਡੀ ਉਪਚਾਰਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿੰਚਾਈ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੰਯੰਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਸੀਵਰੇਜ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2031 ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰਿਆਵਰਣ

ਆਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ

- ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 01 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤਕ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤਕ, ਦੋ ਵਾਰ 'ਆਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ' ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ-ਪਹੀਆਂ ਨਿਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮ-ਵਿਸ਼ਮ (ਆਡ-ਈਵਨ) ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਮਿਲੀ।

ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਡੇ

- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ “ਕਾਰ-ਫ੍ਰੀ ਡੇ” ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਇਕ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ‘ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਡੇ’ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਾਲ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਰੋਡ ਤਕ ਸੀ।
- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਪਰਿਵਹਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਕਾਰ-ਫ੍ਰੀ ਡੇ’ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ।

ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕੰਮ ਯੋਜਨਾ

- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਹਨ-
- ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਮਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਦਰਪੁਰ, ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਬੀਟੀਪੀਐਸ) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਬੀਟੀਪੀਐਸ ਤੋਂ ਫਲਾਈ-ਐਸ਼ ਚੁਕਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਅਤੇ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ।
- ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ।
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡੀਜਲ ਜੇਨਰੇਟਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਪਬੰਧੀ ਹੈ।
- ਪਟਾਖਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ (ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)
- ਪਰਿਵਹਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ

- ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਓਵਰਲੇਡ ਟੱਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਰੋਕ, ਐਸੇ ਟੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਰੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ ਪੀਯੂਸੀਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ। ਬਿਨਾਂ ਢੱਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਗਰੀ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ।
- 7 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ 2016 ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਤੋੜਫੋੜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
- ਡੀਪੀਸੀਸੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੂੜਾ, ਸੁਕੀਆਂ ਪਤੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ।
- ਕੂੜਾ, ਸੁਕੀਆਂ ਪਤੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ।
- ਸੈਨੇਟਰੀ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿਚ ਫਾਇਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਾਲਿਕਾ ਨਿਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼।

ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ

- ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਪਹਿਆਂ ਵਾਹਨਾਂ, ਚਾਰ-ਪਹੀਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਿਹੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਈ-ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਹਨ ਵਿਭਾਗ ਦਵਾਰਾ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੈਟਰੀ ਚਾਲਿਤ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਰੁ-30,000 ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਚਰਾ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

- ਕਚਰਾ-ਵੇਸਟ ਪਦਾਰਥ, ਪੱਤੀਆਂ, ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਡੀਪੀਸੀਸੀ ਨੇ “ਡੋਲਹੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ” ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਕ ਫੇਸਬੁਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 9717593574 ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵੈਟਸਐਪ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸੁਕੀਆਂ ਪਤੀਆਂ, ਕਚਰਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਆਦਿ ਸਾੜਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਤੇ ਐਸ-ਓ-(ਬਾਗਵਾਨੀ) ਅਤੇ ਸੈਨਿਟੇਸ਼ਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇ ਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਕਸ ਐਂਡ ਗਾਰਡਨਸ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਡੀਪੀਜੀਐਸ) ਠੋਸ ਵੇਸਟ ਦੀ ਡੰਪਿੰਗ ਨਾਲ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਫਲਡ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਨ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਰਿਵਹਨ

ਬਸ ਡਿਪੂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ

- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਡੀਟੀਸੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਪਰਿਵਹਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਬਸ ਡਿਪੂ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 11 ਬਸ ਡਿਪੂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਖ-ਵਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 3000 ਨਵੀਆਂ ਬਸਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਲ ਅਗ੍ਰਸਰ ਹੈ।

ਕਲਸਟਰ ਬੱਸਾਂ

- ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਲੂ ਲਾਈਨ ਬਸਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਬਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਸਟਰ ਬਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 11,000 ਬਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਕਿਤ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ, ਡੀਟੀਸੀ ਹਰੇਕ ਕਲਸਟਰ ਰੂਟ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਬਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਲਸਟਰ ਬਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 1700 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2017 ਤਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ 225 ਅਤੇ ਬਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ

- ਮਹਿਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਡੀਟੀਸੀ ਬਸਾਂ ਵਿੱਚ (ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ) 1269 ਹੋਮਗਾਰਡ, 1818 ਸਿਵਿਲ ਡਿਫੇਂਸ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ 170 ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 'ਮਾਰਸ਼ਲ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਬਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਫੀਡਰ ਬਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
- 26 ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
- ਡੀਟੀਸੀ ਬਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ 200 ਲੇਅ ਫਲੋਰ ਬਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਟੀਸੀ ਅਤੇ ਕਲਸਟਰ ਬਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਟੋ ਪਰਮਿਟ

- ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਸਟ ਮਾਈਲ ਕਨੇਕਟਿਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਓਆਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 10,000 ਨਵੇਂ ਆਟੋ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਫੇਜ਼-4

- ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈਟਵਰਕ 189 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ। 140 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਲਈ ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕੰਮ 11-04-2011 ਨੂੰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਜੂਨ 2017 ਤਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਦਾ ਕੁਲ ਨੈਟਵਰਕ 330 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 116 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅਠ ਕਾਰੀਡੋਰ ਵਾਲੇ ਮੈਟਰੋ ਫੇਜ਼-4 ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਫੇਜ਼-4 ਦਾ ਕੰਮ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਿਕਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ

- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਪਰਿਵਹਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ, ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਬਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਿਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਸਟਰ ਬਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਿਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ।

ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਗਰਿਕ ਪਰਿਵਹਨ ਸੇਵਾਵਾਂ

- ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਵਿਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਲਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਨਿਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਰਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆਰਸੀ, ਅਸਥਾਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਦਿ ਸੇਵਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

“ਪੁੱਛੋ” ਐਪ

- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, “ਪੁੱਛੋ” ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਮਨ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐਸ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਟੈਕਸੀ ਜਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੁਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਆਟੋ ਫਾਈਂਡਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਐਪ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ...

ਕਿਰਤ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ

- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਦਿਵਸ ਮਈ 2015 ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੁਭਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਘਟੇ ਘਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ

- ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰ-155214 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਤ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ 5 ਸੌ 63 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ

- ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 58-08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 13,831 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਅਭਿਆਨ

- ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ 150 ਵਾਰ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ 1114 ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ ਨਾਲ-ਹੀ-ਨਾਲ 123 ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ/ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸ਼੍ਰਮਜੀਵੀ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿਤ

- ਸਰਦ ਰੁਤ ਇਜਲਾਸ 2015 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ “ ਸ਼੍ਰਮਜੀਵੀ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰਮਜੀਵੀ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।
- ਆਨ ਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ-ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 11 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਪ ਐਂਡ ਇਸਟੈਬਲੀਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਨੂੰ

ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

- ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਪਤਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਰਤ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ

- ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 18 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 7 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ 1) ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 2) ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਸਹਾਇਤਾ 3) ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ਿਆ 4) ਅੰਤਮ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ 5) ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਸਹਾਇਤਾ 6) ਕਲਾਸ 1 ਤੋਂ 12 ਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 7) ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ
- ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕੁਲ 4 ਲਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ 5 ਸੌ 76 (411576) ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼੍ਰਮਿਕਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 1,68,044 ਲਾਈਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
- ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁਲ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੇਸ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
- ਭਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ
- ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਲਦ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਸਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਵੇ। ਅਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।



ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ



- ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਥਾਨੀ ਨਿਕਾਇਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 200 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਤਮ-ਪ੍ਰਮਣੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2015 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਤੁਰੰਤ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਲਕ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਤਕਾਲ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। 20 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੂ-ਅਭਿਲੇਖ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਸਥਾ ਭੂ-ਲੇਖ (ਦਿੱਲੀ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੂਚਨਾ) ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੇ ਆਰਓਆਰ (ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ।
- 186 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 33458 ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ 1 ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਬਾਅਦ

ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੇ ਆਰਓਆਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

- ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਾ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਆਰਓਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਚੋਵੀ ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ

- ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਸ਼ੁਲਕ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਉਪ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵੰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਸਰਚ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਈ-ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਆਲ ਸੈਂਟਰ
- ਰਾਜਸਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਵਿਚ ਈ-ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
- ਇਹ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਵੇਰੇ 09:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6.00 ਵਜੇ ਤਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਈ-ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ 33 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਤਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।



ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ



- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 2500 ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਾਭਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲਾਭਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਲ 19.46 ਲਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਚਿੰਨਤ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਭਗ 72 ਲਖ ਲੋਕ ਇਸ ਲੜੀ ਨਾ ਜੁੜ ਚੁਕੇ ਹਨ।
- ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 40 ਐਫਪੀਐਸ (ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ) ਤੇ ਪਾਈਲਟ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਯੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਐਫਪੀਐਸ (ਪੀਓਐਸ) ਨੂੰ ਬਾਯੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ

- ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਾਭਆਰਥੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

- ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਖਾਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਐਸਐਮਐਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੋਰਟਲ

- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਨਾਵਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਾਭਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।



ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

- ਰਾਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ/ਕਾਲ ਸੇਂਟਰ ਨੰਬਰ 1967
- ਰਾਸ਼ਨਰ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਮਾਪਤ
- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਐਫਪੀਐਸ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

دو سال بے مثال دو سال بے مثال دو سال بے مثال

راشن لائے لیجانے کی نگرانی

● بھارتیہ کھادنگم سے دہلی راجیہ ناگرک آپورتنی گم لمیٹڈ کو خوراک کی آپورتنی گم لمیٹڈ کو خوراک کی فراہمی کرنی ہوتی ہے۔ اس کی نگرانی آن لائن پورٹل کے ذریعہ سے کی جاسکتی ہے۔ کارڈ ہولڈروں کو ان کاراشن ہموار طریقے سے ملنا یقینی بنانے کے لئے آن لائن نظام سے راشن کارڈ استعمال کرنے والوں اور راشن تقسیم کا ایک ساتھ ہی راشن تقسیم کے بارے میں جانکاری کا ایس ایم ایس مل جاتا ہے۔ اس سے راشن کی کالا بازاری پر روک تھام میں مدد ملتی ہے۔

نیا خوراک تحفظ پورٹل

● دہلی سرکار نے عوامی تقسیم نظام کو آسان بنانے کے ارادے سے لوگوں کیلئے ایک پورٹل تیار کیا ہے۔ عوامی تقسیم نظام کو صاف شفاف بنانے کیلئے اس نئے پورٹل کے ذریعہ فائدہ اٹھانے والوں کو جوڑا جا رہا ہے۔



راشن کارڈ استعمال کرنے والوں کی جانکاری پورٹل پر مہیا کرائی جا رہی ہے۔

● راشن ہیپ لائن / کال سینٹر نمبر: 1967

● راشن تقسیم میں وقت کی پابندی ختم

● دہلی سرکار نے محکمہ کے انسپکٹر کے ذریعہ سنیالت تقسیم اسٹارٹ نظام کو ختم کر کے ایک مضبوط قدم اٹھایا ہے۔ راشن تقسیم کا کام اب ہر مہینے کے پہلے دن شروع ہوتا ہے اور راشن کارڈ صارف مہینے بھر راشن دکانوں سے راشن حاصل کر سکتا ہے۔ نئے نظام سے راشن کارڈ صارف اور ایف پی ایس لائسنس رکھنے والوں کو بڑی راحت ملی ہے۔

عوامی تقسیم نظام



● دہلی سرکار عوامی تقسیم نظام کی لگ بھگ 2500 منظور شدہ راشن دکانوں کے ذریعہ سے فائدہ حاصل کرنے والوں کو کھانے کی اشیاء تقسیم کر رہی ہے۔ محکمہ خوراک و رسد نے کھانے کی اشیاء پورا کرنے اطمینان بخش اور تقسیم نظام کڑی کو مضبوط کرنے کیلئے سبھی فائدہ اٹھانے والوں کو سو فیصد آدھار کارڈ سے جوڑا ہے۔ دہلی میں قومی خوراک تحفظ قانون 2013 کے تحت کل 1946 لاکھ راشن کارڈ ٹیگ ہے۔ دہلی میں اب تک لگ بھگ 72 لاکھ لوگ اس سیریز سے جوچکے ہیں۔

دہلی میں 40 ایف پی ایس (راشن کی دکان) پر پائلٹ پروجیکٹ کے تحت بائیومیٹرک پہچان پتر کے بعد راشن جاری کیا جا رہا ہے۔ سبھی ایف پی ایس (پی او ایس) کو بائیومیٹرک پہچان کرنے کی نظم سے جوڑا جا رہا ہے۔ جس سے راشن کی کالا بازاری کو روکا جاسکتا ہے۔

راشن کارڈ پورٹیلٹی

● راشن کارڈ پورٹیلٹی کو تجرباتی بنیاد پر دہلی چھاونی ودھان سبھا حلقہ میں لاگو کیا گیا ہے۔ کارڈ پورٹیلٹی کے تحت ایک چناؤ حلقہ میں موجود کسی بھی راشن دکان سے فائدہ اٹھانے والے راشن حاصل کر سکتا ہے۔

دو سال بے مثال دو سال بے مثال دو سال بے مثال

- متعلقہ ضلع آفسوں کے عوام خدمات مرکز سے آراو آر حاصل کئے جا سکتے ہیں۔ یا انہیں ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔ یہ خدمت چوبیس گھنٹے موجود ہے۔

اسٹامپ اور اندراج

- جنوری 2016 سے اسٹامپ آن کا مجموعہ آن لائن کے ذریعہ شروع کر دیا گیا ہے۔
- مارچ 2016 سے سب رجسٹر دفتر میں ہونے والے جائیداد کے رجسٹریشن کا کام آن لائن کر دیا گیا ہے۔ اسکے ساتھ ہی عوام کو جائیداد کی تفصیل کی جانکاری لینے کیلئے سرچ کی سہولت مہیا کروادی گئی ہے۔
- ای ضلع پر یوجنا کیلئے عوام کال سینٹر ٹیکس محکمہ کے ہیڈ آفس میں ای ضلع پر یوجنا کے تحت عوام کے سوالوں، شکایتوں، مشوروں کی معلومات عوام کیلئے کال سینٹر کا قیام
- یہ کال سینٹر صبح 09.30 بجے سے شام 6.00 بجے تک اتوار کو چھوڑ کر سبھی کام کے دنوں میں کام کرتا ہے۔ اس کال سینٹر میں موجود خدماتوں سے متعلق میں سبھی سوالوں کے جواب دیئے جاتے ہیں۔

انتظامیہ سدھار



- مختلف محکموں مقامی جگہوں اور دوسرے سرکاری تنظیموں کی جانب سے مانگے جانے والے 200 درجوں کے حلف ناموں کی ختم۔ اب اس کی جگہ پر خود تصدیق کر کے دینے کو اپنایا گیا ہے۔ مارچ 2015 میں سرکار کے قائم ہونے کے ایک مہینے کے اندر ہی کابینہ نے اس بارے میں فیصلہ لیا تھا۔ اس فیصلہ کو فوراً ہی لاگو کیا گیا۔
- فوراً شادی رجسٹریشن فیس کو -/10000 روپے سے گھٹا کر 1000 روپے کر دیا گیا ہے۔ یہ فوراً بنیاد پر اپنی شادی کو رجسٹریشن کروانے والے جوڑوں کیلئے ایک بڑی راحت ہے۔ 20 جنوری 2017 کو اس جانب میں ایک مسودہ بھی جاری کی گئی۔
- ایک آدھونک ویاپک اور صاف شفاف زمینی ریکارڈ پروسیج نظام کو ترقی یافتہ کرنے کیلئے بھو اے سی لیکھ کمپیوٹری کرن پر یوجنا کا کام کیا گیا۔ محکمہ ٹیکس کے اندر پرستھ جیو مضامین (دہلی زمینی ریکارڈ نوٹس) نے عوام کی سہولت کیلئے ڈیجیٹل دستخط والے آراو آر (ریکارڈ کا حق) جاری کرنے کی سہولت مہیا کروائی۔ 186 گاؤں کے 33458 کھاتوں کی زمین کے زمینی ریکارڈ ڈیجیٹل شکل میں مہیا۔ دہلی سرکار کے سبھی ضلع آفسوں میں 1 نومبر 2016 کے بعد ڈیجیٹل ریکارڈ والے کھاتوں کیلئے صرف ڈیجیٹل دستخط والے آراو آر ہی جاری کئے جا رہے ہیں۔



دو سال بے مثال دو سال بے مثال دو سال بے مثال

مزدور

مزدور وکاس مشن کا گٹھن

- قومی مزدور دیوس مئی 2015 کے موقع پر مزدور وکاس مشن کی شروعات کی گئی۔ اس کا اہم مقصد کم از کم مزدوری کو صحیح ڈھنگ سے لاگو کرنا اور تعمیر و دیگر مزدوروں کو فلاحی یोजनाؤں کی شکل میں ملنے والی اقتصادی مدد میں اضافہ کرنا ہے۔

مزدوروں کیلئے ہیلپ لائن

- تعمیر مزدوروں کیلئے ہیلپ لائن نمبر 155214 شروع کیا گیا ہے اس مزدور ہیلپ لائن پر پچھلے دو سالوں میں 25 ہزار 5 سو 63 شکایتیں / جانکاری متعلق کال ملی اور سبھی کا تسلی بخش ڈھنگ سے نپٹارا کیا گیا۔

مزدوروں کو مدد

- پچھلے دو سالوں میں محکمہ مزدور کے ذریعہ مختلف مزدور قانونوں کے تحت 58-08 کروڑ روپے کی رقم کی مدد 13831 مزدوروں کو دیا گیا ہے۔

بچہ مزدوری سے پاک ابھیان

- پچھلے دو سالوں میں ضلع محکمہ مزدور کی ٹاسک فورس کے ذریعہ 150 ہزار چانک چھاپہ مارکر 1114 بچہ مزدور کو آزاد کرایا۔ ساتھ ہی ساتھ 123 کارخانوں / تنظیموں کو سیل کر دیا گیا جہاں ان بچوں سے کام کرایا جارہا تھا۔ اور ان سے 15 لاکھ 40 ہزار روپے، جرمانہ کے طور پر وصول کیا گیا۔

ورکنگ صحافیوں کا مفاد

- سرمائی اجلاس 2015 کے دوران ودھان سبھا میں ورکنگ صحافیوں اور دیگر اخبارات ملازمینوں کے حق میں منصوبہ تبدیلی قانون پاس کیا گیا۔ قانون میں ورکنگ صحافیوں اور دیگر اخبارات کے ملازمینوں کو

ان کی جائز مزدوری سمیت کافی معاوضہ یقینی کرنے کا منصوبہ ہے۔
• آن لائن خدمات - محکمہ کے ذریعہ 11 خدماتوں کو ترجیح کے آدھار پر آن لائن کیا جا رہا ہے جس میں سے دو خدمات شاپ اینڈ اسٹیلیٹمنٹ ایکٹ کے تحت لائسنس اور فیکٹری بلڈنگ تعمیر یोजना لائسنس کو آن لائن کر دیا گیا ہے۔

• آن لائن خدمات شروع کرنے کے بعد بھون تعمیرات یोजना کی قبولیت میں صرف تین دن کا وقت لگتا ہے۔ جبکہ پہلے یہ قبولیت 3-4 مہینوں میں دی جاتی تھی۔ اسی طرح فیکٹری لائسنس جاری کرنے کا وقت بھی 3 مہینے کے بجائے صرف ایک ہفتہ ہو جائے گا۔

ورکرز فلاح و بھبود بورڈ

• بورڈ کی 18 یोजनाؤں کے ذریعہ تعمیراتی مزدوروں کو مالی مدد مہیا کی جاتی ہے۔ اس میں سے 7 یोजनाؤں کا فائدہ رجسٹریشن کی تاریخ سے ہی ملنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ یोजनाں ہیں۔ (1) پرستی مدد، (2) معذور مدد، (3) ایکس گیس، (4) آخری بار داہ تدفین مدد، (5) اچانک موت مدد، (6) کلاس 1 سے 12 تک تعلیم کیلئے مدد، (7) حمل ٹھہر جانے کے وقت میں دی جانے والی مدد

• بورڈ میں کل 4 لاکھ 11 ہزار 5 سو 76 (411576) لائیو افراد ہیں۔

• بورڈ کے ذریعہ اب تک کل 2200 کروڑ روپے مختص اور سود کے شکل میں ذخیرہ کئے گئے۔

بلڈنگ اور دیگر تعمیراتی مزدوروں کا بیمہ

- تعمیراتی مزدوروں کیلئے صحت بیمہ یोजना جلد لائی جائے گی۔ اس کے لئے بیمہ کمپنیوں سے بات چیت کی جا رہی ہے۔
- یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ سبھی طرح کی فلاحی یोजनाؤں سے متعلقہ بیمہ مزدوروں کے کھاتے میں سیدھے جائے۔ اور مزدوروں کے رجسٹریشن کیلئے بینک اکاؤنٹ ضروری کیا جائے گا۔



مثال دو سال بے مثال دو سال بے مثال

آٹو پر مٹ

- دہلی میں آٹو رکشہ کی مسافروں کیلئے لاسٹ مائل کنکٹوٹیٹی میں اہم کردار ہیں۔ سرکار نے ایل او آئی اسکیم منظور کی ہے۔ اور اس سال 10000 نئے آٹو پر مٹ جاری کئے گئے ہیں۔

دہلی میٹرو فیز-4

- ڈی ایم آر سی کا موجودہ نیٹ ورک 189 کلومیٹر کا ہے۔ 140 کلو میٹر کیلئے ڈی ایم آر سی کے تیسرے فیز کا کام 11-04-2011 کو منظور ہو گیا تھا۔ یہ کام جون 2017 تک پورا ہونے کی امکان ہے۔ اس کے بعد میٹرو ریل کا کل نیٹ ورک 330 کلومیٹر ہو جائے گا۔ سرکار نے 116 کلو میٹر کے آٹھ کوریڈور والے میٹرو فیز-4 کو نظریاتی شکل سے منظوری دی ہے۔ فیز-4 کا کام دسمبر-2021 تک پورا ہونے کی امکان ہے۔

الیکٹرانک ٹکنگ سسٹم

- دہلی سرکار نے عوامی ٹرانسپورٹ نظام کو نیک عمل، آسان اور شفاف بنانے کی کوشش کے تحت اسٹیج کیرج بسوں میں الیکٹرانک ٹکنگ مشینوں کی شروعات کی ہے۔ سبھی کلسٹر بسوں میں اب الیکٹرانک ٹکنگ مشینیں ہیں۔

آن لائن ناگرک ٹرانسپورٹ خدمات

- ڈرائیونگ لائسنس کیلئے اپائنٹمنٹ اور فیس بھرنے آن لائن سہولت پہلے ہی شروع کی جا چکی ہے۔ تاکہ عمل آسان ہو اور وقت کی بچت بھی ہو سکے۔ دہلی میں گاڑی سوفٹویئر کو لاگو کر دیا گیا ہے۔
- جس میں ڈیلر کی جانب سے نجی گاڑیوں کا رجسٹریشن آر سی جاری کیا جانا، ڈبل کیٹ آر سی، مقامی رجسٹریشن، ملکیت کی منتقلی دیگر خدمات شامل ہیں۔

"پو چھو" ایپ

- سرکار نے شہر میں ٹیکسی اور آٹو رکشا خدمات کو آسان بنانے کیلئے "پو چھو" لانچ کیا ہے۔ یہ خدمات ان آٹو رکشا اور ٹیکسی ڈرائیوروں کا ایک کامن سرور سے جوڑنے میں قابل بنائے گی۔ جس کی گاڑیوں میں جی پی ایس لگا ہوا ہے اس کے بعد مسافر اپنے اسمارٹ فون کے ذریعے ٹیکسی یا آٹو رکشا گھر بیٹھے بک کر سکیں گے۔ آٹو فائینڈر آپریشن کے ساتھ ساتھ مسافروں کی سہولت کیلئے یہ ایپ کرایہ بھی بتائیگا اور سفر کا لائیو اپ ڈیٹ بھی دے گا۔

ٹرانسپورٹ

بس ڈپو کی تعمیر

- دہلی سرکار اپنے ڈی ٹی سی بیڑے کو بڑھانے کیلئے عہد بند ہے۔ جو ہمارے روزمرہ گاڑیوں نیٹ ورک کا حصہ ہے۔
- بس ڈپو کیلئے کافی جگہ موجود نہ ہونے کی وجہ بسوں کی تعداد میں اضافہ نہیں کیا جا رہا تھا۔ سرکار نے اس معاملے کو فوری طور پر لیا اور اب تقریباً 415 کروڑ روپے کی لاگت سے بس ڈپو بن کر تیار ہونے کے مختلف مراحل میں ہے۔ ان کوششوں کی وجہ سے سرکار اب لگ بھگ 3000 نئی بسوں کے ٹنڈر جاری کرنے کی جانب گامزن ہے۔

کلسٹر بسیں

- غیر محفوظ مانی جانے والی بلیو لائن بسوں کو عہد بند طریقے سے ہٹانے کا کام پورا ہو چکا ہے۔ انکی جگہ پر سرکار نے کلسٹر بس سسٹم کے تحت نئی بسوں کی تعداد میں بڑھوتری کرنے شروعات کر دی ہے۔ ان نئی یو جٹا کے تحت 11000 بسوں کی نوآئیں بیڑوں میں ڈی ٹی سی ہر کلسٹر روٹ میں 50 فیصدی بسوں کا آپریشن کرے گا اور باقیوں کا آپریشن نجی کمپنیوں کے ذریعہ کیا جائے گا۔
- پچھلے سال کے دوران کلسٹر بس اسکیم کے تحت 200 سے زیادہ بسوں کو شامل کیا گیا جس سے اس اسکیم کے ماتحت آنے والی بسوں کی کل تعداد 1700 ہو گئی ہے۔ مارچ 2017 تک اس اسکیم کے ماتحت اور 225 اور بسوں کو شامل کیا جائے گا۔

خواتین کی حفاظت

- خواتین مسافر کی حفاظت کیلئے ڈی ٹی سی بسوں میں (شام اور رات کی شفٹ میں) 1269 ہوم گارڈ، 1818 سول ڈیفنس والیونٹیر اور 170 اضافی اسٹاف کو مارشل کی شکل میں تعینات کیا گیا ہے۔
- اسٹیج کیرج بسوں اور میٹرو فیڈر بسوں میں خواتین کیلئے 25 فیصدی سیٹیں ریزرو کی گئی ہیں۔
- 26 روٹوں پر مصروف ترین وقت کے دوران لیڈیز اسپیشل بسیں چلائی جا رہی ہیں۔
- ڈی ٹی سی بسوں میں سی سی ٹی وی کیمرہ 200 لوکلورز بسوں میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگانے کی ابتدائی منصوبہ پوری ہو گئی ہے۔ سرکار نے سبھی ڈی ٹی سی اور کلسٹر بسوں میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔

دو سال بے مثال دو سال بے مثال دو سال بے مثال

ماحولیات

طاق - جفت اسکیم

- دہلی میں بھاری آلودگی اور ٹریفک جام کو دیکھتے ہوئے دہلی سرکار نے 01 جنوری سے 15 جنوری 2016 تک اور 15 سے 30 اپریل 2016 تک، دو بار طاق - جفت اسکیم لاگو کی۔ اس اسکیم کے تحت چار پہیہ انجی گاڑیوں کو ان کے جوڑ بیجوڑ (طاق - جفت) رجسٹریشن نمبر کے آدھار پر ایک ایک دن چھوڑ کر دہلی کی سڑکوں پر چلنے کی اجازت تھی۔ اس اسکیم کو دنیا بھر سے وسیع تعریف ہوئی۔

کار فری ڈے

- دہلی سرکار نے 22 اکتوبر 2015 کو پہلی بار "کار فری ڈے" اعلان کیا۔ اس دن وزیر اعلیٰ اروند کچر یوال نے خود ایک سائیکل ریلی کی اگوائی کی۔ جس میں 1000 سے زیادہ سائیکل سواروں نے حصہ لیا۔ جس نے لوگوں کو اپنی انجی گاڑیوں کے استعمال کیلئے حوصلہ افزاء کیا۔ پہلے کار فری ڈے کا دائرہ لال قلعہ سے بھگوان داس روڈ تک تھا۔
- دہلی سرکار نے پبلک گاڑیوں خدمات کے استعمال کو حوصلہ افزائی کرنے کیلئے تین مہینوں تک کار فری ڈے کا انعقاد کیا۔ یہ ان کئی اُپایوں میں سے ایک ہے جو شہر کے فضائی آلودگی سطح کو کنٹرول کرے گا۔

فضائی آلودگی کنٹرول

کام یوجنا

- سرکار نے دہلی میں فضائی آلودگی کی بُری حالت کو قابو میں کرنے کیلئے نیچے لکھے ہنگامی قدم اٹھائے ہیں۔
- دہلی آلودگی کنٹرول سمیتی کے ذریعہ بدر پور تھرمل پاور (بی ٹی پی ایس) کی سبھی اکائیوں کو بند کیا گیا۔ بی ٹی پی ایس فلائی - ایش اٹھانے پر فوراً روک اور فلائی - ایش اسٹورج پر پانی کا چھڑکاؤ۔
- سڑکوں پر جھاڑو لگانے سے پہلے پانی کا چھڑکاؤ۔
- ناگزیر خدمات کو چھوڑ کر دہلی میں طرح کے ڈیشل جنریٹریٹ کے استعمال پر پابندی ہے۔
- پٹاخوں پر پابندی (مذہبی پروگراموں کو چھوڑ کر)
- ٹرانسپورٹ محکمہ اور ٹریفک پولیس نے سرحدوں پر اور دہلی کے اندر

کارروائیاں تیز کی ہیں۔ جیسے اوور لوڈیڈ ٹرکوں کے داخلے پر روک، ایسے ٹرکوں کے داخلے پر روک جن کا منزل دہلی نہیں ہے ان گاڑیوں کیخلاف کارروائی جن کے پاس قانونی پی پی سی سی نہیں ہے، حقیقی شکل سے آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں کیخلاف کارروائی۔ بنا ڈھکے تعمیر سامان لے جانے والے ٹرکوں کیخلاف کارروائی۔

- 7 نومبر 2016 سے 14 نومبر 2016 تک دہلی میں سبھی تعمیرات، توڑ پھوڑ کی کام کاج پر پابندی لگایا گیا۔
- ڈی پی سی سی، ایس ڈی ایم اور پولیس کے آفیسروں کے مخصوص دل بنا کر کوڑا، سوکھی پتیاں، جلانے کیخلاف کارروائی۔
- کوڑا، سوکھی پتیاں، جلانے کے کمپیوٹر اپلی کیشن مینی مو نیٹرنگ۔
- سینٹری لینڈ فل سائٹوں میں آگ پر قابو کرنے کیلئے سبھی پالیکا دفنوں کو ہدایت۔

بیٹری سے چلنے والی گاڑیوں کو بڑھاوا

- آلودگی سے پاک ای گاڑیوں کو بڑھاوا دینے کے ناکص العمل سے، سرکار نے دو پہیہ، چار پہیہ گاڑیوں اور ساتھ ہی ای رکشہ جیسے مختلف قسم کے ای - گاڑیاں خریدنے پر سبسڈی اسکیم کی اعلان کیا ہے۔
- محکمہ ٹرانسپورٹ کے ذریعہ قانونی اور راشٹر راجدھانی خطہ دہلی میں رجسٹریشن بیٹری سے چلنے والی ای رکشا مالک کو -/30000 روپے کی ایک مشنت سبسڈی دی جاتی ہے۔

کھلے میں کچرا جانے والوں پر کارروائی

- کچرا - فضلہ اشیاء، پتیاں جلانے کو روکنے کیلئے ڈی پی سی سی نے "دہلی پالیوشن کنٹرول کمیٹی" کے نام سے ایک فیس بک اکاؤنٹ کھولا ہے اور ساتھ ہی مو بائل نمبر 9717593574 کے ساتھ ایک واٹس ایپ اکاؤنٹ بھی شروع کیا گیا ہے۔
- سوکھی پتیاں، کچرا، پلاسٹک دیگر جلانے پر روک لگانے میں لا پرواہی پر ایس او (باغبانی) اور سینی ٹیشن انسپکٹر کو شخصی طور سے ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔
- دہلی پارک، اینڈ گارڈن سوسائٹی (ڈی پی جی یاس) ٹھوس فضلہ کی ڈمپنگ سے یمنہ کے باڑھ کے میدانوں کی صفائی کر اور یمنہ فلڈ بینکوں کو انکے بینادی طور میں واپس لا کر عزت مآب نیشنل گرین ٹریبونل کے ہدایتوں کا عہد بند ہے۔

دو سال بے مثال دو سال بے مثال دو سال بے مثال

سیوریج



دہلی سرکار نے 20000 لیٹر تک مفت پانی دینے کا اپنا وعدہ لگا تار دوسرے سال بھی پورا کیا

- شہر میں پانی کی بڑھتی مانگ کو دھیان میں رکھتے ہوئے گرمی کے موسم میں تقریباً 900 ایم جی ڈی پینے والے پانی کا زیادہ پیداوار حاصل کیا گیا ہے۔
- پانی کے کمی والے علاقوں میں پانی کی آپورتی بڑھانے کیلئے ٹیوب ویل واٹر اے ٹی ایم کی تنصیب کے ساتھ ساتھ 700 ٹینکروں کے موجودہ بیڑے میں اسٹینلس اسٹیل کے 250 نئے پانی کے ٹینکر شامل کئے گئے ہیں۔
- ویب بنیاد آن لائن ٹینکر مانیٹرنگ نظام کو صاف شفاف بنایا گیا ہے۔ تاکہ لوگ اپنے محلوں میں آنے والے ٹینکروں کا اور ان میں آنے والی پانی کی مقدار کا پتہ لگا سکیں۔
- دورا کا اور بوانا میں بالترتیب 50 اور 20 ایم جی ڈی صلاحیت کے دو پانی صفائی کے پلانٹ چالو کئے گئے ہیں۔ جس سے 20 لاکھ لوگوں کو فائدہ پہونچے گا۔
- پوری دہلی میں کئی نئے زمین کے نیچے پانی مہیا اور بوسٹر پمپنگ سیٹوں کو چالو کیا گیا ہے۔ جس سے 25-30 لاکھ لوگ سیراب ہو رہے ہیں۔

سیوریج

- 6 سیوریج صفائی کے پلانٹوں کو چالو کرنے سے سیوریج ٹھیک کرنے کی صلاحیت بڑھ کر 604 ایم جی ڈی ہو گئی ہے۔
- دہلی میں 200 کلو میٹر ٹرنک سیوریج نیٹ ورک کے ساتھ 7700 کلو میٹر کا سیوریج ورک ہے۔ 135 شہری گاؤں میں سے 130 گاؤں کو سیوریج سہولت، مہیا کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ، 189 گرامین گاؤں میں سے 45 گاؤں میں سیوریج سہولت، مہیا کرنے کا کام پورا کر لیا گیا ہے۔
- دہلی گیٹ میں 15 ایم جی ڈی کا سیوریج صفائی پلانٹ (ایس ٹی پی) اور یمنواہار میں 25 ایم جی ڈی صلاحیت کا سیوریج صفائی پلانٹ چالو کیا گیا ہے۔ یمناندی پانی کے معیار میں سدھار کیلئے نئے ایس ٹی پی کی تنصیب معیاری تکنیک کے ساتھ کی جا رہی ہے۔
- 39 ایم جی ڈی صاف پانی کا استعمال سیپاچی باغبانی کیلئے اور ساتھ ہی الیکٹرک استعمال میں رسد کیلئے بھی کیا جا رہا ہے۔
- سیوریج ماسٹر پلان 2013 کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔

- پانی کے 1256883 گھریلو صارفین خاندانوں نے 20000 لیٹر فی ماہ تک کی مفت پانی سپلائی کا فائدہ اٹھایا۔ اس کے باوجود دہلی جل بورڈ کا ٹیکس بڑھا۔ ٹیکس مجموعہ 2014-15 میں 1219-49 کروڑ روپے تھا جو 2015-16 میں بڑھ کر 1549-94 کروڑ روپے ہو گیا۔ 2016-17 (28-12-2016 تک) 869-13 کروڑ روپے ٹیکس کی شکل میں جمع ہوئے۔
- 01-04-2015 کو فعال صارفین کی جو تعداد 19-20 لاکھ تھی وہ بڑھ کر 21-66 لاکھ ہو گئی ہے۔ ان سبھی صارفین کی سہ ماہی بلنگ یقینی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
- پانی اور سیوریج ٹیکس جو 494 روپے فی مربع میٹر تھا، اس میں بھاری کٹوتی کر کے 100 روپے فی مربع میٹر کر دیا گیا ہے۔
- 309 غیر قانونی کالونیوں میں ٹل - پانی مہیا کرانی گئی ہے۔ اس قسم کے کل 1797 غیر قانونی کالونیوں میں سے ٹل - پانی مہیا والی کالونیوں کی تعداد 1103 ہو گئی۔

دو سال بے مثال دو سال بے مثال دو سال بے مثال

بجلی

سے زیادہ بجلی کٹوتی نہ کیا جائے۔ اور اگر ضرورت ہو تو بھی

1 گھنٹے سے زیادہ مدت کے لئے کٹوتی نہ کریں۔

• بجلی تنازعات کے حل اسکیم۔ کافی وقت سے زیر التوا صارفین شکایتوں اور جھگڑوں کو حل کرنے کے لئے سرکار نے عوام کے حق میں بجلی جھگڑا سلجھانے کیلئے اسکیم شروع کی ہے۔ اس یو جنا کے ذریعہ سے لگ بھگ 35000 صارفین سیدھے طور پر مستفیض ہوئے ہیں۔

• توانائی صلاحیت ایل ای ڈی بلب۔ صارفین کو 93 روپے فی بلب کی در سے چار ایل ای ڈی بلب مہیا کرائے جارہے ہیں۔ لگ بھگ 65 لاکھ ایل ای ڈی بلب صارفین کو تقسیم کئے جا چکے ہیں۔

• لگ بھگ 1-32 لاکھ ایل ای ڈی اسٹریٹ لائٹ دہلی میں لگائی گئی ہیں۔

• سولر روف ٹاپ پالیسی کے تحت سرکاری عمارت کی چھتوں پر اور بجلی تقسیم کرنے کی جگہوں پر لگائے جارہے ہیں۔ دہلی میں نیٹ میٹرنگ کے تحت قریب 200 سمسٹی توانائی تقسیم کرنے کی جگہوں پر کئے گئے ہیں۔ بہترین ٹرانسمیشن یوٹیٹی ایوارڈ۔ دہلی ٹرانسکو لمیٹڈ کو بہتر بجلی خدمات کو مہیا کرانے کیلئے سال 2016 میں بھارت کا سب سے بہترین پاور ٹرانسمیشن یوٹیٹی ایوارڈ سے نوازا گیا۔

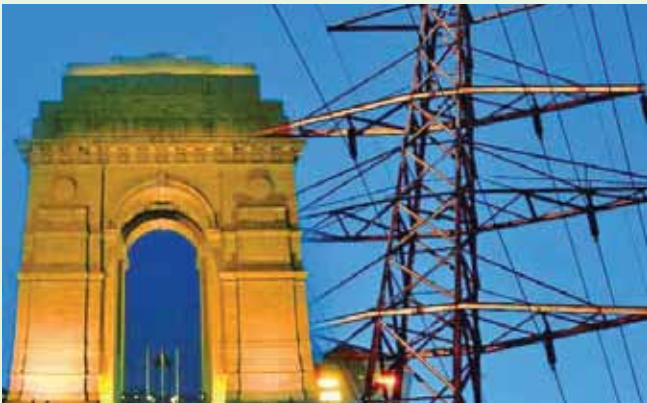
• الیکٹرک پیداوار کے حلقے میں دوسرا مقام۔ راشٹریہ ارجا تحفظ 2016 کے تحت دہلی سرکار کی الیکٹرک پیدا کرنے والی کمپنی پی پی سی ایل کو سال 2016 کیلئے دوسرے سب سے بہتر الیکٹرک پیدا کرنے والی کمپنی کا انعام ملا۔



• پچھلے دو سالوں کے دوران بجلی کی قیمتوں میں کسی بھی طرح کی بڑھوتری نہیں ہوئی۔

• سرکار کے ذریعہ سال 2015 سے راجدھانی دہلی کے گھریلو صارفین کو فی ماہ 400 یونٹ تک بجلی کی کھپت پر 50 فیصدی کی سبسڈی مہیا کی جارہی ہے۔

• بجلی کٹوتی کی شکایتوں کے پنڈانے کیلئے 24 گھنٹے چلنے والے کال سینٹر کی تنصیب کی گئی ہے۔ ڈسکام کو یہ یقینی بنانے کو کہا گیا ہے کہ ضرورت



دو سال بے مثال دو سال بے مثال دو سال بے مثال

صحت خدمات

شہری صحت مرکز، (پی یو ایچ سی)، 39 آیور ویدک، 19 یونا نی و 101 ہومیو پیتھک ڈسپینسری، 43 موبائل کلینک، 170 اسکول ہیلتھ کلینک ہیں۔

- صحت خدمات مہیا کرنے کا کام 25000 سے زیادہ ڈاکٹر اور منسلک صحت اسٹنٹ کرنے والے کر رہے ہیں۔

نئی پھل

- ایم بی بی ایس کورس میں 100 سیٹوں کی صلاحیت کے ساتھ نئے میڈیکل کالج، بابا صاحب امبیڈکر میڈیکل کالج، روہنی میں کام کاج شروع۔
- دہلی کے 10 سرکاری اسپتالوں میں مفت میڈیکل اور سی ٹی اسکین۔
- سبھی مریضوں کیلئے مفت دوائیاں اور میڈیکل ٹیسٹ
- دہلی کے رہائشیوں کیلئے یونیورسل ہیلتھ کیئر انشورنس اسکیم شروع کرنے کی یوجنا۔ اس اسکیم کا حد ڈائیگنوسٹک پروسیجر اور سرجری سمیت کیش لیس طریقے سے اسپتال میں بھرتی ہونے کی سہولت مہیا کرنا ہے۔
- دہلی سرکار کے ذریعہ "ہوم ٹو ہسپتال کیئر" ایمبولنس سروس اسکیم کی شروعات کی گئی ہے۔ اس اسکیم کے تحت ٹیکس ایمبولنس گھر کے دروازے پر سبھی قسم کے میڈیکل ایمرجنسی کیلئے مفت ایمبولنس خدمات مہیا کی جا رہی ہیں۔



دہلی سرکار نے مفت دوا، مفت جانچ کا اپنا وعدہ پورا کیا

- سرکار نے 36 ملٹی اسپیشلسٹی اسپتالوں کے ساتھ مضبوط صحت خدمات کی ساخت تیار کی ہے۔ ان میں چھ سپر اسپیشلسٹی اسپتال، بلڈ بینک اور بلڈ اسٹوریج کی سہولتوں والے 10 اسپتال اور ای ڈبلیو ایس درجہ کیلئے 69 پرائیویٹ اسپتالوں میں 731 مفت بستر سمیت 11000 سے زیادہ بستر شامل ہیں۔
- دہلی میں 242 یلو پیٹھک ڈسپینسری، 107 عام آدمی محلہ کلینک (پابلیک وبا قاعدگی)، 23 پولی کلینک، 58 سیڈ پرائمری



دو سال بے مثال دو سال بے مثال دو سال بے مثال

تعلیم

- پوری دہلی میں، سمو دایوں، پارکوں، میدانوں، میں 1000 ریڈنگ میل
- 1500 اسکولوں میں گریٹیم کالین سیور (سمرکمپ) کا انعقاد
- مہانگر کے سبھی اسکولوں میں ایک ساتھ دو میگا - پی ٹی ایم منعقد،
- میگا - پی ٹی ایم میں بھاری تعداد میں سرپرستوں کی موجودگی۔

پرائیویٹ اسکولوں پر نکیل

- سرکار نے دہلی کے پرائیویٹ اسکولوں کی نمنا نے ڈھنگ سے فیس بڑھانے پر روک لگائی۔ اس کے لئے سرکاری زمین پر بنے سبھی نجی اسکولوں کا آڈٹ کیا گیا اور پہلی بار اسکولوں نے سرپرستوں کو جمع کی گئی بڑھی فیس لوٹائی
- اقتصادی طور پر کمزور طبقہ کے بچوں کا پرائیویٹ اسکولوں میں داخلے کیلئے آن لائن لائری سسٹم لاگو کیا۔

امبیڈ کر کالج کی تو سب سے

- کرپورا میں امبیڈ کر کالج کا نیا کیمپس کھولا گیا۔ گریجویٹیشن سطح پر چار پڑھائی کیلئے کلاس روم کی شروعات 2100 طلباء کو دو نئے کیمپسوں میں داخلہ دیا گیا۔ سال 2022ء تک طلباء کی تعداد 10000 تک پہنچنے کی امید ہے۔

تو سب سے یوجنا

- آئی آئی آئی ٹی ڈی کے فیز -2 کی تعمیر جون 2017 تک پورا ہونے کی امید ہے۔ جس سے طلباء کے داخلے کیلئے 1400 اضافی سیٹیں 3 مہیا ہوگی۔
- نیتاجی سبھاش انسٹی ٹیوٹ آف ٹکنالوجی کو اپ گریڈ کر نیتاجی سبھاش یونیورسٹی آف ٹکنالوجی بنایا جا رہا ہے اور طلباء کی تعداد 4000 سے بڑھ کر 10000 کی جا رہی ہے۔
- سنگاپور سرکار کی مدد سے قائم کی گئی عالمی سطح مہارت مرکز میں 15-2016 کے دوران نئے کورس شروع کئے گئے ہیں۔
- داخلہ کی حد 400 سیٹوں سے بڑھا کر 900 ہو گئی ہے۔



بنیادی ڈھانچے کی تعمیر

- 8000 نئی کلاسیں (تقریباً 200 اسکولوں کے برابر ساخت کی تعمیر)
- 21 نئے اسکول بلڈنگ
- 54 اسکولوں میں جدید سہولتیں
- سبھی کلاسوں میں گرین بورڈ
- صاف صفائی کیلئے جدید تکنیک کا استعمال
- لڑکوں اور لڑکیوں کیلئے الگ الگ استعمال کیلئے بیت الخلاء
- آراو تکنیک سے مہیا کئے گئے پینے کے پانی کی سہولت
- سبھی اسکولوں میں سی سی ٹی وی حفاظتی کیمرے
- اساتذہ کے اسٹاف روم کا کایا کلپ
- اسکولوں سے آگے کی پڑھائی کیلئے سرکار کی گارنٹی پر 10 لاکھ تک کالون۔

اکادمی کامیابیاں

- چنوتی 2018: سرکاری اسکولوں کے طلباء میں سیکھنے کی کمیوں کو دور کرنے کیلئے مہم
- ٹیچر دیوس سے بال دیوس تک پڑھنے کی سو فیصد صلاحیت - مہم میں ایک لاکھ سے زیادہ بچوں نے پڑھنا سیکھا۔

میں روز موبائل پر مینی فیسٹو

چیک کرتا ہوں: منیش سسودیا

کاج کی خوشبو پوری دنیا میں فیل رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تعمیر مزدوروں کے حق میں جیسے قدم دہلی سرکار نے اٹھائے ہیں، ویسا شاید ہی کہیں ہوا ہو۔ ملک کی آزادی کیلئے قربانی دینے والے شہیدوں کی یاد میں سرکار ایک انوکھی ڈیجیٹل ڈائری بنا رہی ہے۔

وزیر صحت و توانائی ستیندر جین نے دہلی کی صحت اور بجلی خدماتوں میں آئے بدلاؤں کی چرچا کرنے کے ساتھ بتایا کہ جلد ہی دہلی میں 1000 محلہ کلینک اور 100 کینٹین کھل جائیں گی۔ وہیں وزیر خوراک و رسد عمران حسین نے بتایا کہ اب گودام سے راشن نکلتے ہی صارفین کے موبائل پر میسرز جاتا ہے۔

اس موقع پر سبھی وزیروں نے یوجناؤں کو موثر طریقے سے عملی جامہ پہنانے کیلئے سرکاری ملازمین کی جھکر تعریف کی۔ اس موقع پر دو سال کے مکمل ہونے پر دہلی سرکار کے ڈائریکٹوریٹ برائے اطلاعات و تشہیر کے ذریعہ تیار کی گئی ورکنگ رپورٹ بھی جاری کی گئی۔ ■

14 فروری 2017 کو سرکار کے دو سال مدت پورا ہونے پر دہلی سچو ایلیہ میں ایک پروگرام کا انعقاد ہوا۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا اور دیگر وزیروں نے سرکار کی خوبیاں گنوائی اور ادھورے کاموں کو جلد پورا کرنے کا یقین جتایا۔ جناب سسودیا نے کہا کہ روز موبائل پر مینی فیسٹو چیک کرتے ہیں تاکہ پتہ رہے کہ سرکار اپنے وعدے کہاں تک پورا کر پائی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی سرکار ایک سچے کا نام ہے جو عام آدمی کی امیدوں کی طاقت پر کھڑی ہے۔ انہوں نے تعلیم اور دیگر حلقوں میں آئے تمام بدلاؤں کا ذکر کیا۔ ساتھ ہی بتایا کہ وائی فائی سہولت کیلئے بھی سرکار سنجیدگی سے قدم بڑھا رہی ہے۔

اس موقع پر دہلی جل بورڈ وزیر پیکل مشرانے بتایا کہ ایمانداری اور جنون سے ان کی سرکار کام کر رہی ہے۔ دہلی میں پانی کی قلت کو حل کیا گیا ہے اور یمنافائی کو لیکر بھی کئی مہاتوا کا نشی یوجنائیں چل رہی ہیں۔ چار مہینے میں سابق راشٹر پتی ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کا اسمارک بننا بڑی کامیابی رہی۔ جناب وزیر گوپال رائے نے کہا کہ انکی سرکار کے کام





ٹیسٹ مفت کر دیا، سارا علاج مفت کر دیا۔ سبھی غریبوں اور امیروں کیلئے۔ پورے ملک میں یہ اپنی طرح کا پہلا تجربہ ہے، اکیلی مثال ہے۔ آج یہاں سرکاری اسپتالوں میں بھی یوزر چارجز کے نام پر غریبوں سے بھی پیسہ لیا جاتا ہے۔ وہیں دہلی میں سب کیلئے مفت علاج کی سہولت ہے۔ چاہے امیر ہو یا غریب۔

دوستو! ہم رات دن کام کر رہے ہیں لیکن لگتا ہے کہ اگر پورا ملک، سبھی صوبائی سرکاری، مرکزی سرکار، یوم جمہوریہ پرٹھان لیں کہ تعلیم اور صحت کی حالت ٹھیک کریں گے، تو آنے والے دنوں میں ملک بہت ترقی کر سکتا ہے۔ جو بچے سامنے بیٹھے ہیں، وہ بڑے ہو کر ایڈوکیٹ بنیں گے، انجینئر بنیں گے، ہوائی جہاز چلائیں گے اور پوری دنیا میں نام روشن کریں گے۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر میرے تو ایک ہی پیغام ہے کہ پورا کریں گے۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر میرے تو ایک ہی پیغام ہے کہ پورا ملک ٹھان لے کی تعلیم اور صحت بہتر کرنا ہے۔ اچھی بات ہے کہ پرائیویٹ اسپتال ہیں، لیکن سرکار اپنی ذمہ داری سے بچ نہیں سکتی۔ تعلیم اور صحت کی ذمہ داری پرائیویٹ سیکٹر پر نہیں چھوڑ سکتے۔

ہم لوگوں نے دہلی میں پہلا ٹھوس قدم اٹھایا ہے۔ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ دہلی کی عوام سے جس طرح کا ساتھ اور پیار ملتا رہا ہے، اسے دیکھتے ہوئے ہمیں یقین ہے کہ ہم اپنے مشن میں ضرور کامیاب ہوں گے۔

دو سال میں صحتی خدمات میں بہت سدھار ہوا ہے۔ دہلی میں بڑے اسپتالوں کی کمی نہیں ہے لیکن اگر آپ کو چھینک آگئی، بخار اور کھانسی ہو گئی تو آپ کو ایمس جانا پڑتا ہے۔ اتنی بھیڑ کی بنا سفارش علاج نہیں ہو پاتا۔ جب سرکار بنی تو صحت خدمات لڑکھڑائی ہوئی تھی۔ ہم نے محلہ کلینک بنائے جس کی پوری دنیا میں چرچا ہے۔

تعلیم ملنی چاہیئے۔ اور مناسب فیس پر ملنی چاہیئے۔

ہماری سرکار نے پہلی بار پرائیویٹ اسکولوں پر ٹیکس ڈالی ہے۔ انہیں فیس بڑھانے سے روکا گیا ہے۔ نرسری داخلہ میں خوب عطیہ چلتا تھا۔ اس پر روک لگی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سو فیصدی رُک گیا ہے۔ اب بھی

کچھ ایسا کر رہے ہیں۔ داخلہ کیلئے میز کے نیچے سے لے رہے ہیں پیسہ۔ لیکن منیش سودیا ان کو ٹھیک کرنے میں لگے ہیں۔ جلدی ہی یہ گھنونا عطیہ سسٹم ختم ہوگا اور نرسری کے داخلے پوری طرح شفاف ہوں گے۔ اسی طرح سے دو سال میں صحت خدمات میں بہت سدھار ہوا۔ دہلی میں بڑے اسپتالوں کی کمی نہیں ہے لیکن اگر آپ کو چھینک آگئی بخار اور کھانسی ہوگئی تو آپ کو ایمس جانا پڑتا ہے۔ اتنی بھیڑ کی بنا سفارش علاج نہیں ہو پاتا۔ جب سرکار بنی تو صحت خدمات لڑکھڑائی ہوئی تھی۔ ہم نے محلہ کلینک بنائے جس کی

پوری دنیا میں چرچا ہے۔ لندن پیرس سے صحافی دیکھنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ پبلک ہیلتھ سسٹم ڈلیوری میں شاید یہ دنیا کی اکلوتی مثال ہے۔

الٹرا ماڈرن، ایئر کنڈیشن، دوائیں فری، جانچ فری، یہ کلینک ڈیڑھ سال سے چل رہے ہیں اور بہت اچھے چل رہے ہیں۔ بہت جلدی ایک ہزار محلہ کلینک دہلی میں بن جائیں گے۔ دو تین کلو میٹر کے دائرے میں کوئی نہ کوئی محلہ کلینک ملے گا۔ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے بڑے اسپتال نہیں جانا پڑیگا۔

اسکے اوپر پالی کلینک بنائے ہیں۔ 122 پالی کلینک بنیں گے پوری دہلی میں۔ وہیں ہڈیوں، عورتوں، اور بچوں سمیت آٹھ تجربہ کار ڈاکٹر بیٹھے ہیں۔ وہاں پرائیکسز اور الٹراساؤنڈ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بڑی بیماری ہو تو سپر اسپیشلسٹی اسپتالوں میں جاسکتے ہیں۔ دو سال میں ہم نے بدعنوانی پر ٹیکس کسی۔ ہر سرکاری کام میں پیسہ بچایا۔ اس سے دہلی کے سارے سرکاری اسپتالوں میں اب لوگوں کیلئے دوائیں مفت کر دیا،

"بھارت ماما کی جے!"



لیکن پہلے ان کو پروتساہن نہیں ملتا تھا۔ انہیں دوسرے درجے کا ناگرک سمجھا جاتا تھا۔ آج انہیں بدیش میں اور آئی ایم میں ٹریننگ کیلئے بھیجا جا رہا ہے۔ ان کو لگنے لگا ہے کہ ہماری بھی پوچھ ہو رہی ہے۔ انہیں لگنے لگا ہے کہ وہ ملک کا مستقبل بنا رہے ہیں۔ انہیں اساتذہ اور پرنسپلوں نے یہ چینکار کر کے دکھا دیا۔ میں یوم جمہوریہ کے موقع پر انہیں سلام کرتا ہوں۔

مجھے خوشی ہے کہ دہلی میں جو نئے سرکاری اسکول بن رہے ہیں۔ ان میں وہ ساری سہولتیں ہیں جو شاید آپ کو اچھے سے نجی اسکول میں نہیں ملیں

گے۔ سرکاری اسکولوں میں سویمنگ پل بن رہے ہیں۔ لفٹ لگ رہی ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آنے والے وقت میں لوگ نجی اسکولوں سے بچوں کو نکال کر سرکاری اسکولوں میں داخلہ کرائیں گے۔ دہلی کے سرکاری اسکول پوری دنیا کے سامنے ایک مثال ہوں گے۔ نجی اسکولوں میں بھی کئی ہیں۔ جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہم انہیں سلام کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ ایسے ہی نجی اسکول ایسے ہیں جنہوں نے تعلیم کو دھندا بنا لیا ہے۔ جنہوں نے تعلیم کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں وہ تعلیم کے نام پر پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ ہم ان کی بہت مذمت کرتے ہیں۔ ان کے طرز عمل کو ٹھیک کرنا سرکار کی ذمہ داری ہے۔ ابھی تک سرکاری پرائیویٹ اسکولوں پر لگام لگانے میں ہچکچاہٹ تھیں۔ کیونکہ کہیں نہ کہیں سرکار میں بیٹھے لوگوں کو مفاد ان اسکولوں سے جڑا ہوتا تھا۔

لیکن آج ہمارا صرف ایک دلچسپی ہے کہ دہلی کے بچوں کو اچھی

وہ ہماری کیٹ مینٹ تھی۔ صحت کا بجٹ ڈیڑھ گنا کر دیا۔ دو سال میں دہلی میں جس طرح سے کرائی آرہی ہے ایجوکیشن اور صحت میں اس کی چرچا ہر طرف ہے۔ حالانکہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو گیا۔ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ جنہیں ٹھیک کرتے جائیں گے۔ لیکن یوم جمہوریہ پر آپ سب کو خطاب کرتے ہوئے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے ایجوکیشن اور صحت کے حلقے میں سب سے زیادہ کام کیا ہے۔ جب ہماری سرکاری تھی تو کوئی بھی اپنے بچوں کو سرکاری اسکول نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ لوگ پیٹ کاٹ کر بچوں کو پرائیویٹ میں پڑھانا چاہتے تھے۔ سرکاری اسکول میں پینے کیلئے صاف پانی نہیں ہوتا تھا۔ بیٹیوں کیلئے بیت الخلاء نہیں تھے۔ صفائی کا بُرا حال تھا۔ پڑھائی

کی بُری حالت تھی۔ دوستو! ابھی بھی بہت کچھ

کرنا باقی ہے۔ لیکن میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں دہلی کے عوام کو، جن کے ساتھ مل کر منیش سسودیا، ہمارے وزیر تعلیم نے، دو سال میں کرائی کاری بدلاؤ کیا۔ کوشش کی گئی ہے کہ سبھی سرکاری اسکولوں میں پانی ہو۔ صاف پتھرے بیت الخلاء ہوں۔ بچیوں کے الگ بیت الخلاء ہوں۔ صفائی اور حفاظت کا بہتر انتظام کیا گیا ہے۔ پہلے ایک ایک کلاس میں ڈیڑھ۔ دو سو بچے پڑھتے تھے۔ بھلا کوئی ٹیچر اپنے بچوں کو ایک ساتھ کیسے پڑھا سکتا ہے۔ آٹھ سے دس ہزار نئے کلاس روم دہلی میں بنے۔ لیکن یہ ساری باتیں چھوٹی ہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ اسکولوں میں پڑھائی کے سطح میں بہت اچھا بدلاؤ آیا۔ اس کیلئے دہلی سرکار کے سبھی ٹیچرس اور پرنسپلوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے شاندار کام کیا ہے۔

یہ وہی ٹیچرس ہیں جو پہلے بھی تھے، یہ وہی پرنسپل ہیں جو پہلے بھی تھے۔

جب ہماری سرکار بنی تھی تو کوئی بھی اپنے بچوں کو سرکاری اسکول نہیں بھیجنا چاہتا تھا، لوگ پیٹ کاٹ کر بچوں کو پرائیویٹ میں پڑھانا چاہتے تھے، دوستو! ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے لیکن میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں دہلی کے عوام کو، جن کے ساتھ مل کر منیش سسودیا، ہمارے وزیر تعلیم نے دو سال میں انقلابی بدلاؤ کیا،



بھارت ماتا کی جے انقلاب زندہ باد

پہلے سماج سیوا جگہوں میں کام کرتے تھے۔ غریبوں کے بچے میں۔ ہمیں کئی ایسے بچے ملتے تھے جو بہت غریب ہوتے تھے۔ لیکن بڑے محنتی ہوئے تھے۔ ہمیں لگتا تھا کہ اگر بچوں کو اچھی پڑھائی مل جائے تو ہمارے ملک کے لوگ، ملک کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتے ہیں ہمارے ملک کی سب سے بڑی طاقت جائیداد، سرکاری، فلائی اوور، ایئر پورٹ، پہاڑ، ندیاں اور جنگل نہیں ہیں۔ سب سے بڑی طاقت ہے ملک کی عوام، پوری دنیا کی سب سے سمجھدار عوام بھارت میں ہیں۔

ہمیں یہ بھی لگتا تھا کہ اگر ملک کے لوگوں کو اچھی صحت سہولت دے دی جائیں، انہیں صحت مند بنادیں تو وہ ملک کو کہیں سے کہیں لے جاسکتے

ہیں ہماری سرکاری بنی توان دو حلقوں میں ہم نے سب سے زیادہ دھیان دیا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ فلائی سرکار ایجوکیشن اور صحت خدماتوں میں اتنا خرچ کرتی ہے۔ میں اسے خرچ نہیں، مستقبل کیلئے سرمایہ کاری مانتا ہوں۔ کئی گنا پیسہ واپس آجائے گا۔ جب لوگ ہوشیار اور جاگڑ کر ہو جائیں گے۔

پہلے بجٹ کے اندر ہم نے ایجوکیشن کا بجٹ دو گنا کر دیا۔ ملک میں لوگوں کو یقین نہیں ہوا۔ بہت ساری این جی او اور ایس پیرٹ، اس پر مکالمہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی آتے تھے کی ایجوکیشن پر بجٹ کو دس۔ بیس فیصدی بڑھا دو۔ ہم نے سو فیصدی بڑھا دیا۔

گزشتہ دو سالوں میں بہت سارے تجربے ہوئے، کھٹے، میٹھے، اچھے برے، آج میں ایک ایسی بات رکھنا چاہتا ہوں جو سارے ملک کیلئے اہمیت کا حامل ہے۔ اگر پورا ملک اسے اپنالے، تو بڑی تیزی کے ساتھ ملک کی ترقی ہو سکتی ہے۔

دہلی اور ملک کے سبھی شہریوں کو یوم جمہوریہ کی بہت بہت مبارکباد۔ ہر سال ہم لوگ یوم جمہوریہ مناتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کس طرح مجاہدین آزادی نے انگریزوں سے لڑ کر ملک کو آزاد کرایا تھا۔ کس طرح انہوں نے پارلیامنٹ میں بیٹھ کر ہمیں اتنا اچھا آئین دیا۔ بابا صاحب کے قیادت میں۔ اسی دن 26 جنوری 1950 کو بھارت جمہوریہ بنا۔ اتنے سالوں میں ملک کو تمام کامیابیاں ملیں اور تمام ایسے حلقے بھی ہیں جن میں کام کرنا باقی ہے آج سے دو سال پہلے دہلی کے لوگوں نے ایک بہت اچھا کام کر کے دکھایا۔ ابھی تک کچھ چندہ سیاسی پارٹیاں ہی

چنناؤ لڑتی تھیں۔ چنناؤ میں پیسے کا کھیل ہوتا تھا۔ ایک عام آدمی سوچتا تھا کہ سیاست غنڈوں کا کام ہے۔ غلط لوگوں کا کام ہے۔ عام آدمی سیاست میں آنے سے کتراتا تھا۔ لیکن دو سال پہلے دہلی کے لوگوں نے یہ خیال بدل دیا۔ دہلی نے ساری پارٹیوں کو نکار کر کہا کہ اب سرکار عام آدمی چلائے گا۔

دو سال پہلے دہلی کے لوگوں نے ایمانداری، سچائی، کو ووٹ دیا۔ عام آدمیوں اور عام عورتوں کو دہلی ودھان سبھا پہنچا کر دہلی چلانے کی اجازت دیا۔ پچھلے دو سالوں میں دہلی میں عام آدمی کی سرکار چل رہی ہے۔ اس دوران بہت سارے تجربے ہوئے۔ کھٹے میٹھے، اچھے، برے

آج میں ایک ایسی بات رکھنا چاہتا ہوں جو سارے ملک کیلئے اہم ہے۔ اگر پورا ملک اسے اپنالے، تو بڑی تیزی کے ساتھ ملک کی ترقی ہو سکتی ہے۔ میں منیش جی اور دوسرے کئی ساتھی، سیاست میں آج سے





یوم جمہوریہ پر وزیر اعلیٰ کا خطاب دہلی میں ایجوکیشن اور صحت کے حلقے میں ہوئی کرانٹی

دہلی میں یوم جمہوریہ تقریب ایک دن پہلے ہوتا ہے اس بار 25 جنوری کو چھتر سال اسٹیڈیم میں ہوئے رنگارنگ پروگرام کے بعد دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کچر یوال نے اپنے خطاب میں ایک سنے کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی سبھی سرکاریں اگر تعلیم اور صحت کی حالت بہتر بنادیں تو عام لوگ ملک کو بہت آگے لے جاسکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دہلی میں ان دونوں حلقوں میں کرانٹی کاری سدھار ہوا ہے۔ پیش ہے وزیر اعلیٰ کے خطاب کا لکھا ہوا حصہ:

गणतंत्र दिवस समारोह की झलकियाँ



गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली की झाँकी



डॉ. जयदेव षड़ंगी, निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 द्वारा प्रकाशित
एवं आकांक्षा इम्प्रेशन्स, 18/36 स्ट्रीट नं. 5, रेलवे लाइन साइड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-05 द्वारा मुद्रित